

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

अजमेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com



फोन:- 2627612, 2427249 फैक्स:- 0145-2624665

वर्ष: 30

संख्या: 8

प्रभात

अजमेर, गुरूवार 7 अगस्त, 2025

आर.जे./ए.जे./73/2015-2017

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कराने के लिए स्पीकर के ओएसडी सुप्रीम कोर्ट जायेंगे?

दूसरी ओर, एफआईआर दर्ज कराने के लिए याचिका दर्ज कराने वाले प्रार्थी शेखर मेवाड़ा व कैलाश राम ने सुप्रीम कोर्ट में “केविएट” फाइल की, 5 अगस्त को इस मामले में

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6, अगस्ता। एक अहम घटनाक्रम में, अब तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट और न्यायाधीश समीर जैन ने 4 अगस्त को ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया था।

इससे भी ज्यादा चौंकाते और स्तब्ध कर देने वाली बात यह है कि राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव शर्मा को ओम बिड़ला ने दिल्ली बुलाया था, जहां उन्होंने बिड़ला और राजीव दत्ता, दोनों से मुलाकात की।

संभवतः यह पहला अवसर है, जब किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उस आरोपी से मुलाकात की है, जिसके

■ जैसा कि विदित ही है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश समीर जैन ने, लोकसभाध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता के खिलाफ ‘ह्यूमन ट्रेफिकिंग’ के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश चार अगस्त को पारित किये थे।

■ अजीबोगरीब बात यह भी है कि कांग्रेस ने भी किन्हीं कारणों से इस प्रकरण में चुप्पी साधने का निर्णय सा ले लिया है। क्योंकि, जब किसी कनिष्ठ कर्मचारी ने इस मामले की खबर, पीसीसी की वैबसाइट पर डाली तो तुरन्त आदेश आ गया, पार्टी के उच्चतम स्तर से, कि प्रकरण की स्टोरी वैबसाइट पर नहीं दिखाई जाए।

खिलाफ राज्य के हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया हो।

हालांकि मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, यह केवल कयास ही है, लेकिन पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों में इस बात को लेकर

खासी चर्चा और उत्सुकता है कि लोकसभा अध्यक्ष ने डीजीपी को क्या निर्देश दिए होंगे।

सूत्रों के अनुसार, कथित रूप से मानव तस्करी के आरोपों का सामना कर रहे राजीव दत्ता अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि

हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के आदेश को रद्द कराया जा सके। इसके लिए वे एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल कर रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं, शेखर मेवाड़ा और कैलाश राम ने, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए तथा गड़बड़ी की आशंका के कारण पहले ही, 5 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है, ताकि बिना उनका पक्ष सुने कोई फैसला न हो सके।

राजस्थान और दिल्ली की सत्ता के गलियारों में दत्ता के इस मामले को लेकर काफी चर्चा और दिलचस्पी देखी-सुनी जा रही है।

दिलचस्प बात यह है कि किसी भी कांग्रेस नेता ने अब तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया

नयी दिल्ली, 06 अगस्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत यहां बने केन्द्रीय सचिवालय भवनों में से एक कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर उनके साथ केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल भी थे। इस दौरान मोदी ने कर्तव्य भवन का दौरा किया और यहां बनायी गयी सभी सुविधाओं का निरीक्षण

■ 50 हजार वर्ग मीटर में फैला यह भवन पूर्णतया ईकोफ्रेंडली है, और कई प्रमुख मंत्रालयों के कार्यालय इसी भवन में बनाए जाएंगे।

भी किया।

यह लगभग एक लाख 50 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर है, जिसमें दो बेसमेंट और सात तल (भूतल 6 तल) हैं। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय विभाग और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महेश जोशी की जमानत याचिका पर ईडी की बहस पूरी

जयपुर, 6 अगस्ता। राजस्थान हाईकोर्ट में जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े ईडी प्रकरण में आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर ईडी की बहस पूरी हो गई है। अदालत ने मामले में प्रति-जवाब पेश करने के लिए याचिकाकर्ता को 8 अगस्त का समय दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने ये आदेश महेश जोशी की जमानत याचिका पर

■ याचिकाकर्ता 8 अगस्त को प्रति जवाब पेश करेंगे।

सुनवाई करते हुए दिए।

ईडी की ओर से याचिकाकर्ता की जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रकरण में एसीबी की ओर से दर्ज अन्य एफआईआर में याचिकाकर्ता की भूमिका को बताया गया है। वहीं, याचिकाकर्ता के बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से इस राशि की लौटाना भी बताया जा रहा है, तो राशि लौटाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती है। याचिकाकर्ता और उसके बेटे ने विभाग की टेंडर प्रक्रिया में रिश्तत प्राप्त की है। इसके अलावा, धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत आरोपी को उस समय ही जमानत दी जा सकती है, जब अदालत इस बात से प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि वह इस अपराध का दोषी नहीं है। यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप ने भारत पर रूस से “ऑयल” खरीदने के एवज़ में 25 प्रतिशत टैरिफ और लगाया

अमेरिका ने ऐसी पैनल्टी चीन पर लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई, हालांकि, चीन भी भारी मात्रा में रूस से “ऑयल” खरीदता है

■ इस बड़े हुए टैरिफ के कारण भारतीय माल अमेरिका के बाजारों से लुप्त हो जाएगा तथा भारत को अन्य मार्केट ढूंढ़ने पड़ेंगे, अपना माल बेचने के लिए।

■ पर, रूस के अलावा अन्य स्रोतों से ऑयल खरीदने का विकल्प नहीं बचा है भारत के समक्ष। क्योंकि, अन्य स्रोतों से ऑयल की खरीद बहुत महंगी पड़ेगी भारत को।

■ भारत का अमेरिका को निर्यात बहुत कम है तथा निर्यात बंद होने से इतना नुकसान नहीं होगा, जितना “ओपन मार्केट” से ऑयल खरीदने से होगा।

■ चीन पर पैनल्टी नहीं लगाने से ट्रंप की “टी.ए.सी.ओ.” (ट्रंप आलवेज़ चिकन्स आउट) की छवि को और स्पष्ट और मजबूत कर देता है।

बढ़ जाएंगी।

ट्रंप ने यह घोषणा ऐसे समय में की है, जब अमेरिका की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत चल रही है। ट्रंप रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं कि वे जल्दी से यूक्रेन में अपना युद्ध समाप्त करें।

चाहे अनचाहे, इस कदम ने भारत

को अमेरिका और रूस जैसी प्रतिद्वंद्वी महाशक्तियों के बीच चल रही भू-राजनीतिक खींचतान के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है, जो यूक्रेन युद्ध को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ रणनीतिक दांव-पेंच खेल रहे हैं। भारत ने ट्रंप की भारतीय निर्यात पर सेकन्डरी प्रतिबंध

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उत्तरकाशी आपदा में 100 से अधिक के मरने की आशंका

आधी रात के बाद बादल फटने से आई बाढ़ से भारी विनाश हुआ कई गांव शेष दुनिया से कट गए हैं

■ गंगोत्री नेशनल हाईवे को भारी नुकसान हुआ है। धराली से 40 किलोमीटर दूर भटवाड़ी के पास ही बैरिकेड लगाकर हाईवे को बंद कर दिया गया है।

■ राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए विमानों से राहत सामग्री गिराई, क्योंकि खराब मौसम और भारी विनाश के कारण राहत व बचाव दल आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

हिस्से धंस चुके हैं या टूट चुके हैं, जबकि कई अन्य हिस्से भूस्खलन के कारण बह गए हैं। फिलहाल यह हाईवे धराली से लगभग 40 किलोमीटर पहले भटवाड़ी के पास बैरिकेड लगा दिए गए हैं।

क्षेत्र में बिजली आपूर्ति, मोबाइल नेटवर्क और अन्य आवश्यक सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इनकी बहाली के प्रयास जारी हैं, लेकिन भारी तबाही और लगातार खराब मौसम के चलते प्रगति धीमी है। गंगनानी के पास

एक पुल पूरी तरह से बह गया है, जिससे प्रभावित इलाका और अधिक अलग-थलग पड़ गया है

राज्य सरकार ने हवाई राहत अभियान शुरू किया है, जिसके तहत हेलीकॉप्टरों से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हुए और प्रभावित लोगों के लिये आवश्यक सामग्री गिरायी जा रही है। मलबे से एक और शव मिलने के बाद, अब तक आधिकारिक तौर पर केवल पाँच मौतों की पुष्टि हुई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और निवासियों को आशंका है

कि मौतों का वास्तविक आंकड़ा कहीं अधिक हो सकता है। जमीन पर काम कर रही राहत टीमें मलबे में फंसे लोगों को तलाश कर रही हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, नुकसान का जायज़ा लिया और पूर्ण सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, हर एक जीवन कीमती है और किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भी हालात का जायज़ा लिया और मुख्यमंत्री धामी से सीधे बात कर संकटपूर्ण स्थिति की जानकारी और सरकारी प्रयासों और उपायों के बारे में अपडेट लिया।

धराली तक वैकल्पिक मार्ग खोलने के प्रयास जारी हैं, लेकिन सड़क (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक अक्टूबर से बहाल होंगी एयर इंडिया की अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

नई दिल्ली, 06 अगस्ता। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया के विमानों का परिचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, हालांकि अब

■ अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद सुरक्षा जांच लंबित होने की वजह से एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय सेवा पर आंशिक रोक लगा दी गई थी।

धीरे-धीरे एयर इंडिया के विमानों की आवाजाही सामान्य होती जा रही है। इस बीच बुधवार को एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के सीईओ कैप्टेन विल्सन ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कैलाश मानसरोवर यात्रा रोकी गई

नैनीताल, 06 अगस्ता। उत्तराखंड के कुमाऊं में बादल फटने का कहर फिलहाल बुधवार शाम को थम गया, लेकिन उसका असर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर पड़ा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा बुधवार को धारचूला से आगे नहीं बढ़ पाई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कैलाश मानसरोवर यात्रा का 48 सदस्यीय चौथा दल मंगलवार को

■ उत्तराखंड में आई आपदा की वजह से यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई है।

पिथौरागढ़ के धारचूला पहुंच गया था। रात्रि विश्राम के बाद, आज दल को उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित पहले आधार शिविर गुंजी पहुंचना था, लेकिन अतिवृष्टि के चलते भूस्खलन होने से धारचूला-लिपुलेख मार्ग कई जगह अवरुद्ध हो गया।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 अगस्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने के अंत में चीन जा रहे हैं, जहाँ वे शंघाई कोऑपेरेशन आर्गनाइजेशन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ रहा है और भारत प्रमुख शक्तियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता के बीच फंसा हुआ है। इस यात्रा की पृष्ठभूमि विशेष रूप से जटिल है, अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाते हुए भारत पर भारी शुल्क लगाए हैं, साथ ही भारत पर रूस से तेल आयात कम करने का दबाव भी बना रहे हैं, जबकि रूस, भारत का लंबे समय से रणनीतिक

साझेदार रहा है। इन घटनाओं ने भारत की कूटनीतिक गुंजाइश को सीमित कर दिया है, जिससे नई दिल्ली के लिए अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में विविधता लाना आवश्यक हो गया है। इस पृष्ठभूमि में, मोदी की चीन पहल को एक रणनीतिक पुनर्संतुलन के रूप में देखा जा रहा है, एक ऐसा कूटनीतिक दांव, जो अमेरिकी दबाव को कम करने में सहायक हो सकता है। भारत भले ही वॉशिंगटन के साथ अपने संबंधों के प्रति प्रतिबद्ध हो, विशेषकर प्रौद्योगिकी, रक्षा और ईंडो-पैसिफिक सुरक्षा ढांचे में, लेकिन बीजिंग के साथ नए सिरे से संवाद एक अधिक संतुलित विदेश नीति का संकेत देता है, जो रणनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती है। यह स्पष्ट संदेश है कि भारत

■ भारत, अमेरिका के साथ टैक्नॉलजी, डिफेंस सहयोग तो चाहता है, पर, क्षेत्रीय मामलों में अपने हितों के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता की इच्छा भी रखता है।

■ साथ ही पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा किये गये नरसंहार वाकिया भी ताज़ा है, भारत के दिलो-दिमाग पर। अतः, चीन द्वारा पाकिस्तान का पक्ष लेना हर मामले में, चाहे वह मामला आतंकवादी गतिविधियों के बारे में ही क्यों न हो, भारत के लिए पीड़ादायक अहसास है।

■ एस.सी.ओ. सम्मेलन में वॉशिंगटन, मॉस्को व बीजिंग के बीच कैसे संतुलन बैठाकर आगे बढ़ा जाए, यह भारत के लिए वाकई में चुनौती है।

■ चर्चा है कि सम्मेलन के दौरान प्र.मंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन व चीन के प्रेंसिडेंट शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर सकते हैं।

प्रतिद्वंद्वी वैश्विक शक्तियों के बीच किसी एक पक्ष का चयन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

हालांकि, यह संवाद कई

जटिलताओं से भरा हुआ है। यह यात्रा उस समय हो रही है, जब कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले में कई भारतीय सुरक्षा कर्मियों और

नागरिकों की जान चली गई। इस घटना ने पाकिस्तान के प्रति चीन के रुख को लेकर भारत की चिंताओं को फिर से उभार दिया है, विशेष रूप से इस बात

CMYK

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

CMYK

विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उपीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

शहरों की बिगड़ती आबोहवा, नागरिकों का स्वास्थ्य ख़तरे में

राजस्थान एक गंभीर पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है। वायु, जल, ध्वनि और औद्योगिक प्रदूषण के साथ-साथ खनन से उत्पन्न धूल ने न केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता को प्रभावित किया है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर भी गहरा असर डाला है। शहरों की बिगड़ती आबोहवा ने सांस लेने में तकलीफ, बीमारियों में वृद्धि और पर्यावरणीय असंतुलन का गम्भीर संकट खड़ा कर दिया है। आज यह संकट केवल बड़े शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रदूषण का प्रभाव तेजी से फैल रहा है। राजस्थान के शहरों में वायु, जल, ध्वनि, औद्योगिक और खनन से संबंधित प्रदूषणों के कारण स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आज वायु प्रदूषण राजस्थान के शहरों में एक गंभीर समस्या बन चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, श्रीगंगानगर, जयपुर, दौसा, कोटा और भिवाड़ी जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब और बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। अप्रैल 2०25 में श्रीगंगानगर में एक्यूआई 321 तक पहुंच गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों से कई गुना अधिक है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में वाहनों की बढ़ती संख्या, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण गतिविधियाँ और खनन से उत्पन्न धूल शामिल हैं। जयपुर, जो पर्यटकों का प्रमुख केंद्र है, में यातायात का दबाव और सड़कों पर उड़ने वाली धूल के कारण पीएम 1० और पीएम 2.5 जैसे महीन कणों की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। ये कण फेफड़ों में प्रवेश कर श्वसन संबंधी बीमारियों जैसे अस्थमा, ब्रॉन्काइटिस और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) को बढ़ावा दे रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष रूप से भिवाड़ी, अलवर और कोटा में, कारखानों से निकलने वाला धुआं और रसायन वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के एक अध्ययन के अनुसार, राजस्थान के शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन जैसे गैसीय प्रदूषकों का स्तर भी बढ़ रहा है, जिससे एक बहु-प्रदूषक संकट उभर रहा है। भिवाड़ी, जो एक औद्योगिक हब के रूप में जाना जाता है, में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत गैर-प्राप्ति वाले शहरों में शामिल है। राजस्थान के छोटे शहरों और कस्बों में भी वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट देखी जा रही है, जो पहले केवल बड़े शहरों तक सीमित थी। निर्माण गतिविधियाँ, सड़कों की मरम्मत और बुनियादी ढांचे के विकास ने भी धूल प्रदूषण के स्तर को की गुना बढ़ा दिया है। विशेष रूप से शुष्क जलवायु और तेज हवाओं के कारण धूल के कण हवा में लंबे समय तक रहते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता और खराब होती है।

वायु प्रदूषण का प्रभाव केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह पर्यावरणीय संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। इसके अलावा, वायु प्रदूषण ने पर्यटन उद्योग पर भी असर डाला है। उदयपुर की प्रसिद्ध झीलें, जो कभी अपनी स्वच्छता और सुंदरता के लिए जानी जाती थीं, अब प्रदूषण के कारण अपनी चमक खोती जा रही हैं। राजस्थान सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसके कारण इसे किसी न किसी रूप से विफल माना ही जाएगा। राज्य में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर, विशेष रूप से हनुमानगढ़, झुंझुनू, श्रीगंगानगर और धौलपुर जैसे जिलों में, जहां 3०0 से ऊपर पहुंच गया है, गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहा है। औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों का धुआं, और पराली जलाना प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (‘सॅड’) के तहत कदम उठाए हैं, जैसे पराली जलाने पर रोक और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना, लेकिन इनका प्रभाव बहुत सीमित रहा है।प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की निगरानी में कमी, औद्योगिक इकाइयों पर सख्ती का अभाव, और पुराने वाहनों पर नियंत्रण की कमी ने समस्या को और गंभीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान सहित अन्य राज्यों से प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर जवाब मांगा है। यह सरकार की निष्क्रियता को तो दर्शाता ही है जनजागरूकता और स्थानीय निकायों के सहयोग की कमी भी एक बड़ी बाधा है। हालांकि, हाल के प्रयासों में राजस्थान पुलिस को पराली जलाने पर निगरानी के लिए अनाज किया गया है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए और सख्त नीतियों, नियमित निगरानी, और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान देना आवश्यक है।

इसी जल प्रदूषण राजस्थान में एक और गंभीर चुनौती है। राज्य में जल संसाधनों की कमी पहले से ही एक बड़ी समस्या है, और उस पर जल प्रदूषण ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित सोबेज और कृषि अपवाह ने नदियों, झीलों और भूजल को दूषित कर दिया है। जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक कचरे के कारण कई गांवों में पानी की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। एक टवीट में जोधपुर के अराबा, डोली और धवा जैसे गांवों में फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक कचरे के प्रभाव का जिक्र किया गया, जहां पानी इतना दूषित हो चुका है कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। राज्य की प्रमुख नदियों, जैसे चंबल और बना, में औद्योगिक और घरेलू कचरे का अंधाधुंध निपटान हो रहा है। कोटा और बूंदी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट जल, जिसमें भारी धातुएं जैसे सीसा, कैडमियम और आर्सेनिक शामिल हैं, नदियों में छोड़ दिया जाता है। ये धातुएं जलीय जीवन को नष्ट करने के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल रही हैं।

आशा की जानी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इमरान प्रतापगढ़ी वाले प्रकरण में दिए गए निर्णय की भावना को समझते हुए अनावश्यक रूप से एफआईआर दर्ज करने का जो सिलसिला कई राज्यों में प्रारंभ हुआ है, उस पर रोक लगेगी।

पाई गई है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण भूजल में धूल और रासायनिक अवशेषों का मिश्रण हो रहा है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में अनुपचारित सोबेज का रिसाव भूजल को और दूषित कर रहा है। यह स्थिति न केवल पीने के पानी की कमी को बढ़ा रही है, बल्कि जलजनित बीमारियों जैसे डायरिया, हैजा और टाइफाइड के मामलों में भी वृद्धि कर रही है। उदयपुर की फतेहसागर और रंगसागर झीलें, जो कभी शहर की शान थीं, अब सीधे-सीधे औद्योगिक कचरे के कारण दूषित हो रही हैं। ध्वनि प्रदूषण के मामलों में तो राजस्थान के शहरों में खतरा और भी तेजी से उभरा है। जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे शहरों में वाहनों, कारखानों, लाउडस्पीकरों और निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न शोर ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। विशेष रूप से त्योहारों और सामाजिक आयोजनों के दौरान लाउडस्पीकरों और पटाखों का उपयोग ध्वनि प्रदूषण को और बढ़ाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, खनन और औद्योगिक गतिविधियों के कारण मशीनों और विस्फोटों की आवाज ने शांत वातावरण को नष्ट कर दिया है। खनन गतिविधियां राजस्थान में प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत हैं। राज्य में मार्बल, ग्रेनाइट, चूना पत्थर और अन्य खनिजों का बड़े पैमाने पर खनन होता है, जिससे धूल और मसबब का उत्सर्जन होता है। उदयपुर, मकाना और राजमर्ग जैसे क्षेत्रों में खनन से उत्पन्न धूल ने हवा और पानी दोनों को दूषित किया है। यह धूल न केवल वायु प्रदूषण को बढ़ाती है, बल्कि फसलों और मिट्टी की उर्वरता को भी प्रभावित करती है। खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियां आम हो गई हैं, जो सिलिका धूल के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होती है। इसके अलावा, खनन से उत्पन्न मलबा नदियों और जलाशयों में बह जाता है, जिससे जल प्रदूषण और बाढ़ का खतरा बढ़ता है।

औद्योगिक प्रदूषण भी राजस्थान के पर्यावरण को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भिवाड़ी, अलवर, कोटा और जोधपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों से निकलने वाला धुआं और रासायनिक कचरा न केवल हवा और पानी को दूषित कर रहा है, बल्कि मिट्टी को भी प्रभावित कर रहा है। ध्वनि प्रदूषण में टेक्सटाइल उद्योगों से निकलने वाला रंगीन अपशिष्ट जल नदियों और भूजल में मिल रहा है, जिससे आसपास के गांवों में पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। कचरे का प्रबंधन तो एक बड़ी चुनौती है ही। शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे का ढेर और उसका अנוचित निपटान पर्यावरण को और अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। जयपुर और कोटा जैसे शहरों में कचरे के ढेर खुले में जलाए जाते हैं, जिससे धूल में जहरीले एंजाइम का उत्सर्जन होता है। प्रदूषण का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी असर डाल रहा है। प्रदूषित हवा और पानी के कारण स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हुई है, जिससे चिकित्सा खर्च बढ़ा है। सिलिकोसिस, कैंसर, खदब रोग और श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, प्रदूषण ने पर्यटन उद्योग को भी प्रभावित किया है।

हालांकि प्रदूषण की इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत राजस्थान के कुछ शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत स्वच्छ ईंधन, जैसे सीएनजी और एलपीजी, को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी के लिए ऑनलाइन सिस्टम स्थापित किए गए हैं, और कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। लेकिन इन नियमों का अनुपालन और कार्यान्वयन अभी भी अपर्याप्त है। जल प्रदूषण को कम करने के लिए, सरकार ने नदियों और जलाशयों की सफाई के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। चंबल नदी की सफाई के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन औद्योगिक अपशिष्ट और सोबेज के निरंतर निर्वहन ने इन प्रयासों को प्रभावित किया है। भूजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग और बाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को स्थापना पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं की कमी एक बड़ी चुनौती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, कुछ शहरों में लाउडस्पीकरों और वाहनों के हॉर्न पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इन नियमों का पालन कम ही देखा जाता है। खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने कुछ क्षेत्रों में अवैध खनन पर रोक लगाने की कोशिश की है, लेकिन भ्रष्टाचार और स्वच्छताही के कारण यह समस्या बनी हुई है। कचरे के प्रबंधन के लिए, कुछ शहरों में रोसाइक्लिंग और कम्पोस्टिंग सुविधाएं शुरू की गई हैं, लेकिन ये प्रयास अभी प्रारंभिक चरण में हैं।

प्रदूषण की इस जटिल समस्या से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकार, उद्योगों, स्थानीय समुदायों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाना, औद्योगिक अपशिष्ट के लिए सख्त नियम लागू करना, और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण जैसे कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। स्थानीय स्तर पर, समुदाय आधारित निगरानी और स्वच्छता अभियान भी प्रभावी हो सकते हैं। राजस्थान की बिगड़ती आबोहवा एक चेतावनी है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो यह संकट और गहरा सकता है। यह न केवल पर्यावरणीय, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी आपदा का रूप ले सकता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि राजस्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को बरकरार रख सके। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे। सामूहिक प्रयासों से ही इस संकट से निपटा जा सकता है, और राजस्थान को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सकता है।

—अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र मोहन शर्मा वरिष्ठ साहित्यकार शिक्षाविद् और चिंतक

“वोकल फॉर लोकल” के आह्वान को राज्य सरकार ने आत्मसात किया

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (7 अगस्त) विशेष.....



हेमन्त सिंह

देश के इतिहास के पन्नों में 7 अगस्त, 19०5 को स्वदेशी आंदोलन के रूप में एक नया अध्याय जुड़ा था, इस दिन कोलकाता के टाउन हाल से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का शंखनाद हुआ था। स्वदेशी को स्वाभिमान से जोड़ने वाले इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष

2०15 में इसे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (नेशनल हैण्डलूम डे) के रूप में मनाने की पहल की।

स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों और खासकर हथकरघा को एक नई चेतना दी। वैसी ही स्वत्व एवं गर्व की छवि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ के विजन में भी झलकती है और यह मंत्र अब भारत के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों का परिचायक भी बन रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के इस ‘वोकल फॉर लोकल’ के आह्वान को आत्मसात किया और अपनी ठोस नीतियों के माध्यम से इसे राजस्थान में नई बनावट दी।

राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कोटा डोरिया की महीनता से लेकर सांगानेर और अजरक प्रिंट तक की परम्परागत कला ने न केवल समृद्ध संस्कृति और सभ्यता का तराना रचा है बल्कि वस्त्र उद्योग के रुप में आज भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था का ताना बाना बुन रही

■ ‘स्वदेशी’ से ‘आत्मनिर्भरता’ तक कालजयी है हमारी विरासत राजस्थान में ‘वोकल फॉर लोकल’ की नई बुनावट है पंच गौरव कार्यक्रम

है। कोटा डोरिया और सांगानेर प्रिंट ने देश की सीमाओं से परे अन्तर्राष्ट्रीय फैशन इंडस्ट्री में अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज करवाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश को आधुनिक टेक्सटाइल उद्योग के नये केन्द्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से ‘राजस्थान टेक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2०25’ लागू की है।

इसके अंतर्गत हैण्डलूम जैसे ट्रेडिशन को भी को नवीनतम तकनीक से जोड़ने के लिए पर्याप्त और आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, राज्य सरकार ने कोटा, बालोतरा, भीलवाड़ा, पाली के वस्त्र कला के उत्पादों को पंच गौरव जैसे कार्यक्रम का भी हिस्सा बनाया है।

पंच गौरव कार्यक्रम से पनपती स्थानीय पहचान :- देश

का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते राजस्थान के सभी अंचलों में अलग-अलग परिस्थितिकी, भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं विशिष्ट संस्कृति देखने को मिलती है। राज्य सरकार पंच गौरव कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक जिले में विशिष्ट एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल को प्रोत्साहित कर रही है।

जैसलमेर की खूबसूरत पीलू जाल (वानस्पतिक प्रजाति), प्रतापगढ़ के थेवा आभूषण (उत्पाद) की बेजोड़ कलाकृति, अनोखी महक से सराबोर बीकानेर की मेथी (उपज), सदियों पुरानी धरोहर की छवि को उकेरता नागीर का मीरा स्मारक (पर्यटन स्थल), सिरोही की उकूछ प्रतिभाओं के सामर्थ्य को दर्शाती तीरंदाजी

(खेल) इसके उदाहरण है। स्थानीयता एवं विशिष्टता के संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन, पहचान एवं विकास की पंचधारा से प्रदेश के सभी अंचलों के स्थानीय तत्व अब देश-विदेश में ‘ब्रांड राजस्थान’ बन रहे हैं।

आज 7 अगस्त का दिन हमें यह याद दिलाता है कि आत्मनिर्भरता हमारे देश के लिए आत्मगौरव का विषय है। वैश्विक परिदृश्य में जब आज अन्य देश टैरिफ नीतियों की ओर बढ़ रहे हैं, तब हमारी कालजयी विरासत को संजोते हुए स्थानीय एवं स्वदेशी उत्पादों को विकल्प की बजाए आवश्यक रूप में अपनाने का मंत्र और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की नीतियाँ इसी दिशा में विकास और विरासत की संतुलित करते हुए एक नए एवं समृद्ध राजस्थान की बुनियाद रख रही हैं।

—हेमन्त सिंह (सहा. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी), मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ,

भारत की पेट्रोलियम कंपनियों का महाविलय: यही समय है! सही समय है!



रोटेरियन सुनील दत्त गोयल

आज जब भारत तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, हमें अपने संसाधनों, व्यवस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में वह क्रांतिकारी बदलाव लाना होगा, जो अने वाले देशकों में देश को वैश्विक मंच पर अग्रणी बनाए। पेट्रोलियम सेक्टर इसकी सबसे अहम कड़ी है—और यह वही क्षेत्र है जहाँ बिखराव, विभिन्न ब्रांड, गुणवत्ता की खाइयों, डिस्ट्रिब्यूशन में उलझन और बार-बार सामने आती घण्टीय-चोरियों की खबरें आम हो चुकी हैं।

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कितनी ही सार्वजनिक और निजी कंपनियाँ देश में तेल की आपूर्ति का जिम्मा उठाती हैं। लेकिन क्या ये बिखराव और प्रतिस्पर्धा जनता को वाकई बेहतर सेवा दे पा रही है? हर कंपनी का अपनी कर्पांडीज, अलग-अलग बफर स्टॉक्स, अलग स्टोरेज-ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, अपनी अपनी लॉबी, नेताओं-अफसरों की हिस्सेदारी, पुराना नियम-कायदा, और अंत में पेट्रोल डीजल की गुणवत्ता में अंतर। क्या कभी आपने सोचा—एक शहर में दो ब्रांड के पंप पर, एक ही दिन एक ही पेट्रोल के दाम-गुणवत्ता अलग कैसे हो सकते हैं?

अब समस्या सिर्फ कीमत या उपभोक्ता के भ्रम की नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की लागत व पारदर्शिता की कमी की भी है। रोज़मर्रा के अखबारों की हेडलाइन बनती “पेट्रोल डीजल चोरी”, काला बाजारी, टुक-टैकर घोटाले.. अभी ताजातरीन मामला एक अखबार की फ्रंट पेज पर, पाइप लाइन से कूट आयल चोरी को कई दशकों से चल रही है और एक बड़े माफिया का रूप ले चुकी है जो अपने आप में सिस्टम की चाहिए। जीएसटी को ही ले लीजिए, जब इसके लिए 25 से भी ज्यादा विभागों

कल्पना कीजिए—यदि तीनो पेट्रोलियम कंपनियाँ मर्ज हो जाएँ, उनके संसाधन, पूंजी, पाइपलाइन, रिफाइनरी, डिज़ीनरियर, एविएशन नेटवर्क एक जगह, एक छत्र-छाया के नीचे आ जाएँ, तो कैसे खुलेगा रतक्की का नया रास्ता! कोई ‘प्रीमियम’ और कोई ‘सामान्य’ पेट्रोल की उलझन रहेगी ही नहीं। देश-भर में एक ही क्वालिटी, सबसे बेहतरीन ग्रेड का पेट्रोल-डीजल मिलेगा। लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज की लागत आधी से भी कम, व्यवस्था खातों

किताबों के हिसाब से एकदम पारदर्शी। बफर स्टॉक्स और इमारतेंसी स्टोरेज-जो आज हर कंपनी अलग बनाती-रखती है, वह एक सिस्टम में आ जाएगा।

जब डीलरशिप खुलेगी, तो न पारिवारिक/राजनीतिक सिफारिश चलेगी, न अफसरशाही की पकड़ बचेगी-पारदर्शी नीलामी और ऑक्शन से आम आदमी को भी अवसर।

बाजार में एक ही ब्रांड, एक ही पेट्रोल-तो उपभोक्ता के मन का भ्रम भी दूर और भ्रष्टाचार को भी सीधी चोट। जब वाहनों के लिए एक ही ग्रेड का पेट्रोल-डीजल सरकार उपलब्ध कराएगी, तो प्रदूषण कम करने का लक्ष्य भी यही से साधा जाएगा। ग्रीन हाउस गैस पर नियंत्रण होगा।

वर्टिकल मैनजमेंट: हर डिवाीजन की सीधी जवाबदेही मेगा पेट्रोलियम कंपनी में हर उत्पाद-चाहे वह कूड ऑयल इंपोर्ट हो या की-लुब्रिकेंट, डीजल या एयर टर्बाइन फ्यूल- प्रॉपिन सीएनजी या इलेक्ट्रिकैल्स-उसके लिए अलग-अलग वर्टिकल होगा। हर वर्टिकल के महानिदेशक की स्पष्ट जिम्मेदारी होगी कि इंपोर्ट/खरीद, रिफाइनिंग-प्रोसेसिंग

से लेकर ग्राहक को डिलीवरी तक के हर खर्च-लाभ की सटीक बहीखाते तैयार हो जायेंगे। इस तरह सालाना जब एक विशाल जम्बो बैलेंसशीट बनेगी, तो सरकार और समाज जान पाएगा कि भारत का उत्पादन, उपभोग, टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट और भविष्य की जरूरतें एवं वर्तमान के हालातों से क्बवक होंगे।

अतीत से सबक, भविष्य का रास्ता बहुत लोग कहते हैं-मर्जर है जोखिम का नहीं है” कहता हूँ, यही वह वक़्त है जब सरकार को साहसी निर्णय लेना चाहिए। जीएसटी को ही ले लीजिए, जब इसके लिए 25 से भी ज्यादा विभागों

का एकीकरण हुआ, व्यापारियों से विरोध भी झेलना पड़ा, अफसरों से कड़ा सवाल भी, लेकिन जो एक देश, एक टैक्स, आज हरेक व्यापारी और उपभोक्ता सराह रहा है, वही फायदा पेट्रोलियम में भी मिलेगा।

दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां-भारत को सीखना होगा

दुनिया में सऊदी अरामको जैसी कंपनियाँ (59० अरब राजस्व, 1.8 ट्रिलियन मार्केट कैप), सिनोपेक-चाइना पेट्रोलियम (487 अरब), पेट्रोचाइना, एक्सॉनमोबिल, शेल जैसे ब्रांड, अपनी भव्य एकीकृत व्यवस्थाओं के बल पर वैश्विक रैंकिंग में टॉप पर हैं। जब हमारी कंपनियाँ का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक साथ होगा, तब भारत भी दुनिया की सूची में कहीं आगे बढ़ जाएगा।

दुनिया की शीर्ष तेल कंपनियों का राजस्व और मार्केट कैप:-

सऊदी अरामको (Saudi Aramco) वार्षिक राजस्व: लगभग 590 अरब अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैपिटलाइजेशन: 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर

सिनोपेक (China Petroleum & Chemical) वार्षिक राजस्व: लगभग 487 अरब अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैप: 58 अरब अमेरिकी डॉलर

पेट्रोचाइना (PetroChina) वार्षिक राजस्व: लगभग 486 अरब अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैप: 79 अरब अमेरिकी डॉलर

एक्सॉन मोबिल (ExxonMobil) वार्षिक राजस्व: लगभग 387 अरब अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैप: 445 अरब अमेरिकी डॉलर

शेल पीएलसी (Shell PLC) वार्षिक राजस्व: लगभग 365 अरब अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैप: 2०2 अरब अमेरिकी डॉलर

भारत की मेगा कंपनी की संभावना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास

13,772 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार पूंजीकरण 2,०9,०65 करोड़ रुपये है और इसके पास कुल रिजर्व्स 1,72,716 करोड़ रुपये हैं। आज की तारीख में इसका शेयर भाव 148 है। कंपनी की सालाना बिक्री 7,58,1०6 करोड़ रुपये तक पहुँचती है

और शुद्ध लाभ 13,789 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।

भारत पेट्रोलियम के पास 4,273 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी है, कंपनी का मार्केट कैप 1,45,665 करोड़ रुपये और रिजर्व्स 77,112 करोड़ रुपये हैं। इसके एक शेयर का दाम अब 336 है। बीपीसीएल ने 4,4०,272 करोड़ रुपये की बिक्री की और 13,337 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास 2,128 करोड़ रुपये की इक्विटी, 9०,475 करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण और 49,०16 करोड़ रिजर्व्स हैं। इस समय बाजार में इसका शेयर 425 है। बिक्री 4,34,1०6 करोड़ रुपये की रही जबकि शुद्ध लाभ 6,736 करोड़ रुपये रहा।

तीनों कंपनियों को जोड़ें तो कुल इक्विटी पूंजी 20,173 करोड़ रुपये, कुल मार्केट कैप 4,45,205 करोड़ रुपये और कुल रिजर्व्स 2,98,844 करोड़ रुपये हो जाते हैं। इनकी कुल बिक्री 16,32,484 करोड़ रुपये हैं और मिलाजुला शुद्ध लाभ 33,862 करोड़ रुपये तक पहुँचता है।

यदि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सभी बड़ी भारतीय पेट्रोलियम कंपनियाँ मर्ज होकर एक “मेगा इंडिया पेट्रोलियम” कंपनी का रूप लेती हैं, तो उसके संभावित फ़ायदे और वैश्विक प्रभाव कुछ इस प्रकार होंगे:-

भारत की ‘मेगा कंपनी’ का संयुक्त वार्षिक राजस्व लगभग 200-25० अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है, जिससे वह दुनिया की टॉप-5 तेल कंपनियों की कतार में आ सकती है।

बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) भी बढ़कर लगभग 200-3०0 अरब अमेरिकी डॉलर के लगभग पहुँच सकती है, जिससे भारत वैश्विक मंच पर दिखेगा।

जनता को पूरे देश में एक ही दर और एक ही क्वालिटी का पेट्रोल-डीजल मिलेगा, जिससे उपभोक्ता प्रीतिाय और भ्रष्टाचार दूर होगा।

आज हर राज्य की अपना टैक्स की दरें अलग-अलग होने से उनके बॉर्डर एरिया में जो पेट्रोल पम्प हैं यदि सस्ता है तो बेशुमार बिक्री होती है और अगर बॉर्डर का दूसरा पम्प महंगा है तो उसकी बिक्री नागण्य होती है और इसका उदाहरण राजस्थान -हरियाणा के बॉर्डर पर जा सकता है।

लॉजिस्टिक्स, बफर स्टॉक्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज आदि पर दोहराव ख़तम होगा और अनुमानतः 15-2०

तक कंपनी की प्रॉफिटबिलिटी बढ़ सकती है। सभी का इन्वेस्टी प्रबंधन खर्च मर्जर के बाद आधा हो जाएगा।

एकीकृत कंपनी देश के लिए निवेश, रोजगार, टेक्नोलॉजी और पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर में तेजी ला सकती है।

ग्लोबल स्टेज पर भारत की ब्रांडिंग मजबूत होगी और “वन ब्रांड, वन कंपनी, वन नेशन” का सपना साकार होगा।

ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। भविष्य की जनेरेशन को एक अनुकूल पर्यावरण।

नई कंपनी के बनने से सैकड़ों नई नौकरियाँ, टेक्निकल, ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेशन में शानदार मौके।

इस तरह, भारत की एक विशाल पेट्रोलियम कंपनी विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी बूटने, देश की अर्थव्यवस्था को बूट देने और उपभोक्ता जीवन आसान बनाने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।

देश के लिए, आम जनता के लिए अब यह सिर्फ सरकार के सपने की बात नहीं-यह आम आदमी, टैक्सपेयर, व्यवसायी, किसान, व्यापारी, हर नागरिक के विकास का सपना है। भारत के हर कोने में एक ही दर, एक गुणवत्ता का पेट्रोल-डीजल, पारदर्शी सौदे, स्मार्ट व तेज वितरण। पाइपलाइन से गांव हो या मेट्रो सिटी, गैस-पेट्रोल के बेहतर इस्तेमाल को क्रांति।

अब बदलाव की जरूरत क्या नई चुनौतियाँ नहीं होंगी? जरूर होंगी। बड़े बदलाव कभी भी बिना विरोध या टकराव के नहीं आते, लेकिन अगर लक्ष्य पारदर्शिता, दक्षता, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी और उपभोक्ता को श्रेष्ठ सेवा देना है, तो यह फैसला ऐतिहासिक होगा।

“एक कंपनी, एक ब्रांड, एक क्वालिटी, एक राष्ट्र”-अब समय है भारत को एशिया ही नहीं दुनिया की शीर्ष तेल कंपनियों के साथ बराबरी पर खड़ा देखें। सरकार, विशेषज्ञ, और समाज-सबको आगे आकर इस परिवर्तन की ओर गंभीरता से कदम बढ़ाना होगा।

यदि आपको देश का कोई हिस्सा और विस्तर से चाहिए, हर नागरिक की संचारी, भावनात्मक या तथ्यपरक भाषा में चाहिए-तो आप निर्देश दें।

धन्यवाद,

—रोटेरियन सुनील दत्त गोयल, महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

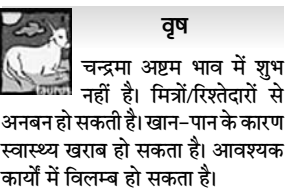
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

जयपुर, राजस्थान



मेघ

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बने लगेगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी।



वृष

संक्षिप्त

स्कूलों में स्टेशनरी वितरण किया

अजमेर, (कासं)। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर अजमेर में अध्यनरत अस्सी और कमला नेहरू राजकीय बालिका विद्यालय हटुंडी अजमेर में अध्यनरत 88 ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को स्वर्गीय प्रेमलता पत्नी एवं स्वर्गीय अमराव सिंह मुणोत की स्मृति में स्टेशनरी काँपी, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर एवं स्केल का वितरण किया। ललित जैन और प्रकाश रंका ने स्टेशनरी वितरण एवं महावीर इंटरनेशनल की गतिविधियों से अवगत कराया। आदर्श नगर स्कूल की प्रधानाचार्या किरण खंडेलवाल व हट्टण्डी स्कूल के प्रधानाचार्य राम प्रकाश चौहान ने महावीर इंटरनेशनल अजमेर केंद्र के सदस्यों एवं दानदाताओं का आभार व्यक्त किया। कइस अवसर पर प्रभात सेठी, दूस्टी पदमचंद जैन, प्रकाश राँका, अशोक कुमार डावरिया, मनोहर गोपाल ईनाणी, बाबुलाल जैन एवं मुखराज जैन, भंवर लाल गुज्रर के साथ दोनों स्कूलों के स्टाफ की उपस्थित रही।

डॉक्टरों ने बचाई जान

अजमेर, (कासं)। बुधवार को अजमेर के जेएलएन अस्पताल के श्वसन रोग विभाग में नावां (नागौर) निवासी 31 वर्षीय मरीज रामनारायण के सांस की नली से दो सेंटीमीटर की सुपारी दूरबीन जांच द्वारा निकाली गई। विभागध्यक्ष डॉ. नीरज गुप्ता ने बताया कि मरीज पिछले एक साल से लगातार खरीज, सीने में दर्द और सांस की परेशानी से जूझ रहा था। मरीज ने पिछले एक साल में कई जगह डॉक्टरों दिखाया लेकिन आराम नहीं आया और परेशानी बढ़ती गई। अंततः मरीज जेएलएन अस्पताल के श्वास रोग विभाग में पहुंचा, जहां चिकित्सकों को छाती के एक्स-रे में सांस की नली में कुछ फंसा होने का संदेह होने पर यूनिट हैड डॉ. रमाकांत दीक्षित एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पीयूष आरोड़ा के निदेशन में ब्रॉकोस्कोपी की जांच की। इससे पता चला कि मरीज के सांस की नली में सुपारी फंसी हुई है। डॉक्टरों की टीम ने ब्रॉकोस्कोपी की मदद से फंसी हुई सुपारी को बाहर निकाला। इससे मरीज को राहत मिली। डॉक्टरों की टीम में सीनियर प्रोफेसर एवं यूनिट हैड डॉ. रमाकांत दीक्षित एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पीयूष आरोड़ा के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. प्रदीप चौधरी एवं डॉ. रणजीत मेघवंशी, रेजिडेंट एवं डॉ. गीता, डॉ. हनुमान शर्मा, डॉ. हसीफा, डॉ. हिमाशु तथा नर्सिंग स्टाफ मानवेंद्र सिंह, गजराज, निवेदिता, मधु शामिल रहें। डॉ. पीयूष आरोड़ा ने बताया कि मरीज अब स्वस्थ है तथा कुछ दिन चिकित्सकों की निगरानी में रहेगा।

धमकी देने का मामला दर्ज

मकराना, (निस) अनाधिकृत रूप से जमीन में खनन कार्य शुरू करने एवं मना करके पर मरने मारने पर उतारू होकर धमकी देने को लेकर एक मामला पुलिस थाना मकराना में दर्ज हुआ है। बोरावड के पादड़ों की ढाणी निवासी देवाराम जाट पुत्र हीराराम ने अपनी दर्ज रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि आरोपी नवाब एवं मुख्तारजी की मार्बल खदान पूर्ण रूप से खत्म हो गई है तथा खदान के आगे एवं पीछे खनन कार्य करने योग्य कोई भी भूमि शेष नहीं बची है एवं गत 12 वर्षों से कोई भी खनन कार्य नहीं चल रहा है। हाल ही में नवाब एवं मुख्तारया खदान को गत दो महीने से उनकी जमीन हड़पने के इरादे से प्रार्थी को तंग व परेशान करते हुए कह रहे हैं। कि उनकी खदान बंद है तो तुम्हारी भी बंद हो रहेगी।

आम सूचना
मेरी दादी थारसी पॉलि बरु जाति भील निवासी अलमास की मृत्यु दिनांक 23.03.2014 को मेरे निवास स्थान पर ग्राम अलमास में हो आई थी। जिसका पृथं मे इन्नाज ग्राम पंचायत देवपुरी में नहीं करवाया था। अब मैं मेरी दादी थारसी भील का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अर्राई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत जिस किसी व्यक्ति को आपति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अर्राई तहसीलदर के सम्मक्ष रखव उपस्थित होकर अपनी आपति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपति स्वीकार नहीं होगी। -प्राणी- कानामन पुत्रते जीत भील,निवासी ग्राम अलमास तहसील अर्राई(अजमेर)

आम सूचना
मेरी पुत्री श्वाना पुत्री रामचन्द जाति भील निवासी ग्राम दादिवा की मृत्यु दिनांक 05.07.1999 को मेरे निवास स्थान पर ग्राम दादिवा में हो गई थी। जिसका पृथं मे इन्नाज ग्राम पंचायत देवपुरी में नहीं करवाया था। अब मैं मेरी पुत्री श्वाना भील का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अर्राई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत जिस किसी व्यक्ति को आपति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अर्राई तहसीलदर के सम्मक्ष रखव उपस्थित होकर अपनी आपति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपति स्वीकार नहीं होगी। -प्राणी- भूरी पॉलिन रामचन्द जाति भील, निवासी ग्राम दादिवा, तहसील अर्राई(अजमेर)

भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन

भीलवाड़ा। जिला कांग्रेस कमेटी भीलवाड़ा के तत्वावधान में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों और दमनकारी कार्यशैली के विरुद्ध जोरदार विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के नाम जापन सौपा गया। कांग्रेस जन मुखजी उद्यान में एकत्रित हुए और रैली के रूप में भाजपा सरकार हाय – हाय ,एवं सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे।

जापन के माध्यम से कांग्रेसजनों ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार पूरी तरह जनविरोधी मानसिकता पर उठी है। भाजपा का शासन जमीनी स्तर पर

■ कांग्रेस जन मुखर्जी उद्यान में एकत्रित हुए और रैली के रूप में भाजपा सरकार हाय – हाय ,एवं सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे

असफल हो चुका है, हर मोर्चे पर विफलता और प्रशासनिक अराजकता का माहौल बन गया है। सरकार सत्ता के मद में चूर होकर आमजन के साथ दोगला व्यवहार कर रही है, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है और जनता की आवाज को दबाने में जुटी हुई है।जिला कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने आरोप लगाते हुए कहा कि

भाजपा की डबल इंजन वाली यह ’’ अकर्मण्य सरकार’’ है, जो विकास और जनसेवा के कार्यों को छोड़कर केवल झूठे वादों, दिखावटी इबैट्स और प्रचार प्रसार में व्यस्त है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार,किसान और मजदूरों की समस्याएं चरम पर हैं लेकिन भाजपा सरकार के मंत्री और नेता जनता के दु:ख-दर्द से पूरी तरह बेपरवाह होकर ’’जनता त्रस्त – सरकार मस्त’’ की नीति पर चल रही हैं। भाजपा शासन में आम आदमी की आवाज दबाने का सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। सत्ता के संरक्षण में अराजक तत्व खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल उठाने वालों पर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। आज प्रदेश की जनता सरकार से जवाब मांग रही

है और आने वाले समय में इस जनविरोधी सरकार को जनता माफ नहीं करेगी। समय रहते सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो जनता के समर्थन के लिये कांग्रेस सड़क पर उतरकर सरकार से जवाब मांगेगी। कांग्रेस प्रवक्ता चन्द्र प्रकाश अमरवाल ने बताया कि जापन देने वालों में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष धर्मेन्द्र पारीक , किसान कांग्रेस के राजेश चौधरी , पूर्व यूथ अध्यक्ष किशन जाट , पीसीसी सदस्य शंकर लाल गाडरी ,मनोज पालीवाल ,सेवादल जिलाध्यक्ष योगेश सोनी , पूर्व सभापति मधु जाजू ,मंजू पोखराना सहित कई कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि भारी संख्या में उपस्थित रहे।

लीज पर दिए जाने हेतु ई.ओ.आई. आमंत्रित

भीलवाड़ा। नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.), भीलवाड़ा द्वारा आर.के. कॉलोनी स्थित सत्यम कॉम्प्लेक्स का रिनोवेशन कराकर इसे आगामी 10 वर्षों के लिए लीज (किराये) पर दिए जाने हेतु इच्छुक संस्थाओं से ई.ओ.आई.आमंत्रित किए गए हैं। सत्यम कॉम्प्लेक्स, गायत्री आश्रम, अजमेर रोड के निकट मुख्य सड़क पर स्थित है, जो व्यवसायिक दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त स्थान माना जाता है। कॉम्प्लेक्स के प्रथम एवं द्वितीय तल को पार्किंग सुविधा सहित किसी भी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, बैंक, ऑफिस अथवा निजी संस्थान हेतु व्यवसायिक उपयोग में लाने के लिए लीज पर दिया जाएगा। यू.आई.टी. द्वारा इस संबंध में ई.ओ.आई. जारी की जा चुकी है तथा इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थाएं 12 अगस्त 2025 सायं 6.00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।

1100 पौधे लगाने का लिया निर्णय

■ इस मौके पर सतगुरु संतोष बाईसा ने 1100 वृक्ष लगाने का निर्णय लिया

नाम आवश्यक रूप से लगाए। पदमश्री हिमताराम भांभू पर्यावरण प्रेमी ने कहा कि एक वृक्ष की आयु हजार वर्ष तक होती है। इसे अनेक पशु पक्षियों का आश्रय मिलता है और मानव को सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन होती है।ऐसे यहां ऐसे में हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। मेड़ता पंचायत समिति प्रधान संदीप चौधरी ने कहा कि वर्तमान

में पेड पौधे ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक है हमें पेड पौषों को लगाने के लिए आगे आना चाहिए। इस मौके पर शिश्त्रयवन अधिकारी ममता जांगिड ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस अभियान में विभाग सहैव तत्पर है। इस मौके पर सदगुरु विनोद बाईसा महाराज ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर पशुपालन विभाग डॉक्टर तेलसीराम चौधरी, पर्यावरण प्रेमी तारचंद मारोठिया, वरीश प्रजापति, रामकिशोर, सुखराम चौधरी, रामलाल सहित मेड़ता शहर, गोदैन, मेड़ता रोड, रोल, डेगाना, लाम्पोलाई क्षेत्र के अनेक लोग मौजूद रहे।

पूर्व छात्रों का स्नेह मिलन समारोह, देश-विदेश से पहुंचे मित्र

परबतसर, (निस)।निकटवर्ती ग्राम किशनसरिया स्थित कैलपूज्य माता मंदिर् प्रांगण में मित्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक अनूठे स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मकराना में सन् 1980 से 1985 तक अध्ययनरत रहे छात्रों द्वारा किया गया, जिसमें देश-विदेश से आए पूर्व छात्रगण भावुक एवं हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में एकत्र हुए।

समारोह के मुख्य संयोजक एवं

मार्बल व्यवसायी अशोक रान्दड़ ने बताया कि इस स्नेह मिलन की रूपरेखा बनें काफी समय से सोशल मीडिया के माध्यम से बन रही थी, जिसे मित्रता दिवस के अवसर पर मूर्त रूप प्रदान किया गया। आयोजन स्थल के रूप में क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल कैलपूज्य माता मंदिर् को चुना गया, जहां सभी ने माता के दर्शन कर आयोजन की शुभ शुरुआत की।

इस स्नेह मिलन में दुबई, दिल्ली, सूरत, नागपुर, कोलकाता, रायपुर,

करीमनगर, हैदराबाद, सिलवासा, उदयपुर, जयपुर, बैंगलुरु सहित देश-विदेश से आए पूर्व छात्रों ने भाग लिया। आगंतुक मित्रों और उनके परिजनों का पारंपरिक स्वागत कर आपसी परिचय, संवाद व आत्मीय क्षणों का आदान-प्रदान किया गया। समारोह में पूर्व छात्रों व कपस के बीच गीत-संगीत, नृत्य व विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिससे वातावरण संगीतमय और उल्लासपूर्ण हो गया। आयोजन के दौरान विद्यालय के वयोवृद्ध शिक्षक

भंवरलाल चौधरी (गुढा) का विशेष सम्मान कर सभी ने अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की।

इस अवसर पर राधेश्याम शर्मा (दुबई), सुनील बिदादा (दिल्ली), केवल छाजेड़ (बेंगलुरु), विनोद कारवा (कोलकाता), शिवकर बुरडक (जयपुर), पवन चौपड़ा (करीमनगर), रमेश अठावाल (दिल्ली), डॉ. अरुण लढा (जयपुर), कमल अठावाल (दिल्ली), विनोद रान्दड़ (उदयपुर), राजेन्द्र मांथनिया

दुग्ध उत्पादकों का सहकार महाकुंभ 24 को अजमेर में

- गहलोत, रंधावा, डोटासरा, जूली व पायलट भी करेंगे शिरकत
- सरकार की उपेक्षा में किसानों पर पड़ रही है, दोहरी मार

दोपहर 12:15 बजे से आयोजित किया जाएगा। अजमेर सरस् डेपरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में आयोजित इस महाकुंभ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकराम जूली, प्रदेश कांग्रेसकमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शिरकत करेंगे। महाकुंभ में राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लाम्बा, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह के साथ ही समस्त

प्रदेश से जिला दुध संघों के अध्यक्ष, सचिव एवं कर्मचारी, किसान, पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादक भी शामिल होंगे। महाकुंभ में पूरे प्रदेश से लगभग पच्चीस हजार किसान, पशुपालक उपस्थित होकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे।

महाकुंभ में दुग्ध उत्पादकों की सात माह से बकाया मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना की राशि 320 करोड़ रुपए एवं मिड डे मील योजना के अंतर्गत इतनी ही राशि बकाया होने पर इसको एक मुश्त जारी करने की मांग

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से संवाद

ब्यावर (निसं)भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर के निर्देशानुसार "विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025-2026" के अंतर्गत मतदाता सूची की गुणवत्ता सुधारने और शत-प्रतिशत पात्र मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 5 अगस्त को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर कमल राम मोना ने की, जबकि उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया उपाध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे।बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) सहित अन्य मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और मतदाता सूची पुनरीक्षण संबंधी प्रक्रियाओं पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए।इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर

नेमीचंद यादव ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बीएलए-द्वितीय (यूथ लेवल एजेंट-2) की भूमिका, घर-घर सर्वेक्षण प्रक्रिया, गणना प्रपत्र भरने की विधि, ऑनलाइन प्रविष्टियों की जिम्मेदारी तथा 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों के पुनर्गठन, विभाजन या नवसूचना की प्रक्रिया पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया।जिला निर्वाचन अधिकारी मोना ने बताया कि यह पुनरीक्षण अभियान पारदर्शिता और सहभागिता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने सभी दलों से आठार किया कि वे समय पर बीएलए-द्वितीय की नियुक्ति करें और क्षेत्रीय स्तर पर मतदाता सूची को अद्यतन एवं शुद्धि रहित बनाने में सहयोग करें। बैठक में एसीईओ गोपाललाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।कार्यक्रम में विशेष रूप से यह ध्यान रखा गया कि सभी राजनीतिक दलों को निर्वाचन कार्यप्रणाली में समान भागीदारी मिले, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास कायम हो।

 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर	
किराये पर वाहन के लिये ई-निविदा सूचना	
बोर्ड कार्यालय से परीक्षा सामग्री परिवहन एवं कार्यालय उपयोगार्थ अन्य कार्य हेतु एक वर्ष के लिये किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु ई-निविदा दिनांक 27.08.2025 अगस्त०३.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। अनुमानित व्यय टेंडर ऑफर के लिये रु. 1.15 लाख, बस ऑफर के लिये रु. 2.0 लाख एवं कार ऑफर के लिये रु. 9.4 लाख है। निविदा प्रत्य, विस्तृत विवरण बोर्ड वेबसाईट www.rajeduboard.raajasthan.gov.in एवं राज्य सरकार के उपायन पोर्टल http://eproc.rajjasthan.gov.in , http://sppp.rajjasthan.gov.in से भी डाउनलोड कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस सम्बन्ध में सहायक निदेशक (सामग्री) के मो.नं. 98280-62662 पर जिला निर्वाचन प्रार्त की जा सकती है। Truckete-UBN.No. SEB2526WSOB00014 Busete-UBN.No.SEB2526WSOB00013 Smallvahanetc-UBN.No. SEB2526WSOB000012	
सचिव	

कार्यालय नगर निगम,अजमेर
इसकायें बाई रमांक के घरा, वसतिन नगर,अजमेर
सर्वोपनिष्ठा सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीनेत्री सुब्बा स्त्री श्री सत्यनारायण रावडा, निवासी 126- ए सर्वश्रम कॉलोनी, अजमेर के द्वारा नाम निगम की वसती कक्षा के आवसीय/व्यावसायिक भूखंड संख्या ११६ के अन्तर्गत २1.33 अर्पण 15/05/1992 को श्री जीने नारायण रावडा व सज्जन रिपोट ससंन कर आयेदन करवाया गया।LSGA/निगम/निग/2025-26/1992 दिनांक 31.07.2025 को नगमनगर हुग अतिरिक्त अवेदन अवेदन किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त भूखंड सूत्र अवेटी श्री सत्यनारायण रावडा पुत्र जीनेनारायण के नाम से रज है। तहसीली लेख नं० 24.01.1998 संलग्न किया गया है। श्री सत्यनारायण रावडा का सत्यापन दिनांक 03.02.2025 को हो चुका है। सज्जन रामान चव के आधार पर श्रीमती गान्धिनी(पुत्री) स्थित वारीर है। उक्त इकण का निष्पत्त तत्काल्य नगर वसति अधिनियम 2009 की धारा 116 के तहत अवेदन है जिसका निष्पत्त धारा 118 के तहत प्रमाणित किया गया है। इस संबंध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आपसी प्रमाणन से 07 अगस्त 2025 के तहत अवेदन के तहत प्रस्तुत दस्तावेजों को अवेदन नाम निगम कार्यालय की कक्षा नगर में उपस्थित के लिए बुला रहा गया है, इस अति में किसी को अवेदन नहीं किया जायेगा।अन्य सारा को अवेटी अवेटी 238 हो को अवेदन के 15 दिवस में नीति अवेटी अवेटी के साथ अपनी आपसी अवेदन कर सकता है बरद निषेध विरुद्धनारा इकण का निषेधन कर दिया जायेगा।
- जीती कुमाराड/अनुपुक्त नगर निगम, अजमेर

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रमनील ल्गणी पुत्र श्री सत्यनारायण निवासी निवासी नम्बर-342, तुषाम नगर, ब्यावर रोड, अजमेर की एक पत्नी अद्वयद जो कि सेटीरीयम के घरा, आम इकण किरानेयग दुकानित व वसित अजमेर में वसित जो दिखतीरुडि गल संख्या- 4 व 5 है दिखत सूत्र इकण 540 निर्माण है दिखतीरुडि की भुजा 103 फुट व पश्चिम भुजा का नाम 58 फुट, उत्तर की भुजा 73 फुट 6 इंच और दक्षिण की भुजा 60 फुट 2 इंचको रूंद में 30 फुट चौड़ा आम सारन है, पश्चिम में बादर सारन, उत्तर में माथर सारन, दक्षिण में उत्तर सारन की रमणी है। जिसको उरुते बादर इकरणनराम रावडा दिनांक 04/09/1992 को श्री जीने नारायण रावडा व सज्जन रिपोट ससंन कर नुक्त के वारिती करवाया है। उरुते बादर व उक्त प्लट पर भंते पक्षधर का मालिकान हक अधिकार व कक्षा है जो नगमपर एवं निष्पत्त वस में वसति वसति सता आ रहा है उक्त सत्यपी पर उरुते बादर किसी हक वसति संरक्षण/का पर पत्नी वसी है उक्त सत्यपी सत सत है। उक्त भुजा का वेदन पर पक्षधर द्वारा किया जा रहा है। यदि उक्त सत्यपी बादर किसी भी सत सता या सत्यि हो किसी तरह का कोई लानत आपति है तो सत सत वसति के वसति पर पक्षधर व सत दस्तावेज व आपति ससंन करें। सता वसति सतत कोई आपति स्वीकार योग्य नहीं जा सकेगी। - पशिवाटी श्री रमनील ल्गणी, मेरवाँलन- 9901242719
-सद्वीर- सत्यन ब्यावर,रावडेकर, मो- 9057373013

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
भूत आवटी / अनतिरि की भुपु पर अवतीरिणीक द्वारा निष्पत्त वसतिरुडि हक सत्य पर के आधार पर नगमनगर हुग आम सूचना का सत्य
-आम सूचना-
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की ग्राम महाकुवसी योजना के आवसीय/व्यावसायिक भूखंड संख्या १३६ अर्पण 236.61 वर्गफुट के अवेटी/अनतिरि श्रीमती मीना गुप्ता पत्नी श्री सत्यनारायण गुप्ता निवासी अजमेर एवं मीनान अर्पण गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता निवासी अजमेर से श्री मीनाजी मीना गुप्ता की मृत्यु दिनांक 15/05/2024 को श्रेने व मृत्यु प्रमाण पत्र व सज्जन रिपोट ससंन कर नुक्त के वारिती करवाया है। अवेटी 2. र्पण 3. अर्पण 4. नृन 5 र्पण 6 अर्पण 7 अर्पण 8 अर्पण 9 अर्पण 10 अर्पण 11 अर्पण 12 अर्पण 13 अर्पण 14 अर्पण 15 अर्पण 16 अर्पण 17 अर्पण 18 अर्पण 19 अर्पण 20 अर्पण 21 अर्पण 22 अर्पण 23 अर्पण 24 अर्पण 25 अर्पण 26 अर्पण 27 अर्पण 28 अर्पण 29 अर्पण 30 अर्पण 31 अर्पण 32 अर्पण 33 अर्पण 34 अर्पण 35 अर्पण 36 अर्पण 37 अर्पण 38 अर्पण 39 अर्पण 40 अर्पण 41 अर्पण 42 अर्पण 43 अर्पण 44 अर्पण 45 अर्पण 46 अर्पण 47 अर्पण 48 अर्पण 49 अर्पण 50 अर्पण 51 अर्पण 52 अर्पण 53 अर्पण 54 अर्पण 55 अर्पण 56 अर्पण 57 अर्पण 58 अर्पण 59 अर्पण 60 अर्पण 61 अर्पण 62 अर्पण 63 अर्पण 64 अर्पण 65 अर्पण 66 अर्पण 67 अर्पण 68 अर्पण 69 अर्पण 70 अर्पण 71 अर्पण 72 अर्पण 73 अर्पण 74 अर्पण 75 अर्पण 76 अर्पण 77 अर्पण 78 अर्पण 79 अर्पण 80 अर्पण 81 अर्पण 82 अर्पण 83 अर्पण 84 अर्पण 85 अर्पण 86 अर्पण 87 अर्पण 88 अर्पण 89 अर्पण 90 अर्पण 91 अर्पण 92 अर्पण 93 अर्पण 94 अर्पण 95 अर्पण 96 अर्पण 97 अर्पण 98 अर्पण 99 अर्पण 100 अर्पण 101 अर्पण 102 अर्पण 103 अर्पण 104 अर्पण 105 अर्पण 106 अर्पण 107 अर्पण 108 अर्पण 109 अर्पण 110 अर्पण 111 अर्पण 112 अर्पण 113 अर्पण 114 अर्पण 115 अर्पण 116 अर्पण 117 अर्पण 118 अर्पण 119 अर्पण 120 अर्पण 121 अर्पण 122 अर्पण 123 अर्पण 124 अर्पण 125 अर्पण 126 अर्पण 127 अर्पण 128 अर्पण 129 अर्पण 130 अर्पण 131 अर्पण 132 अर्पण 133 अर्पण 134 अर्पण 135 अर्पण 136 अर्पण 137 अर्पण 138 अर्पण 139 अर्पण 140 अर्पण 141 अर्पण 142 अर्पण 143 अर्पण 144 अर्पण 145 अर्पण 146 अर्पण 147 अर्पण 148 अर्पण 149 अर्पण 150 अर्पण 151 अर्पण 152 अर्पण 153 अर्पण 154 अर्पण 155 अर्पण 156 अर्पण 157 अर्पण 158 अर्पण 159 अर्पण 160 अर्पण 161 अर्पण 162 अर्पण 163 अर्पण 164 अर्पण 165 अर्पण 166 अर्पण 167 अर्पण 168 अर्पण 169 अर्पण 170 अर्पण 171 अर्पण 172 अर्पण 173 अर्पण 174 अर्पण 175 अर्पण 176 अर्पण 177 अर्पण 178 अर्पण 179 अर्पण 180 अर्पण 181 अर्पण 182 अर्पण 183 अर्पण 184 अर्पण 185 अर्पण 186 अर्पण 187 अर्पण 188 अर्पण 189 अर्पण 190 अर्पण 191 अर्पण 192 अर्पण 193 अर्पण 194 अर्पण 195 अर्पण 196 अर्पण 197 अर्पण 198 अर्पण 199 अर्पण 200 अर्पण 201 अर्पण 202 अर्पण 203 अर्पण 204 अर्पण 205 अर्पण 206 अर्पण 207 अर्पण 208 अर्पण 209 अर्पण 210 अर्पण 211 अर्पण 212 अर्पण 213 अर्पण 214 अर्पण 215 अर्पण 216 अर्पण 217 अर्पण 218 अर्पण 219 अर्पण 220 अर्पण 221 अर्पण 222 अर्पण 223 अर्पण 224 अर्पण 225 अर्पण 226 अर्पण 227 अर्पण 228 अर्पण 229 अर्पण 230 अर्पण 231 अर्पण 232 अर्पण 233 अर्पण 234 अर्पण 235 अर्पण 236 अर्पण 237 अर्पण 238 अर्पण 239 अर्पण 240 अर्पण 241 अर्पण 242 अर्पण 243 अर्पण 244 अर्पण 245 अर्पण 246 अर्पण 247 अर्पण 248 अर्पण 249 अर्पण 250 अर्पण 251 अर्पण 252 अर्पण 253 अर्पण 254 अर्पण 255 अर्पण 256 अर्पण 257 अर्पण 258 अर्पण 259 अर्पण 260 अर्पण 261 अर्पण 262 अर्पण 263 अर्पण 264 अर्पण 265 अर्पण 266 अर्पण 267 अर्पण 268 अर्पण 269 अर्पण 270 अर्पण 271 अर्पण 272 अर्पण 273 अर्पण 274 अर्पण 275 अर्पण 276 अर्पण 277 अर्पण 278 अर्पण 279 अर्पण 280 अर्पण 281 अर्पण 282 अर्पण 283 अर्पण 284 अर्पण 285 अर्पण 286 अर्पण 287 अर्पण 288 अर्पण 289 अर्पण 290 अर्पण 291 अर्पण 292 अर्पण 293 अर्पण 294 अर्पण 295 अर्पण 296 अर्पण 297 अर्पण 298 अर्पण 299 अर्पण 300 अर्पण 301 अर्पण 302 अर्पण 303 अर्पण 304 अर्पण 305 अर्पण 306 अर्पण 307 अर्पण 308 अर्पण 309 अर्पण 310 अर्पण 311 अर्पण 312 अर्पण 313 अर्पण 314 अर्पण 315 अर्पण 316 अर्पण 317 अर्पण 318 अर्पण 319 अर्पण 320 अर्पण 321 अर्पण 322 अर्पण 323 अर्पण 324 अर्पण 325 अर्पण 326 अर्पण 327 अर्पण 328 अर्पण 329 अर्पण 330 अर्पण 331 अर्पण 332 अर्पण 333 अर्पण 334 अर्पण 335 अर्पण 336 अर्पण 337 अर्पण 338 अर्पण 339 अर्पण 340 अर्पण 341 अर्पण 342 अर्पण 343 अर्पण 344 अर्पण 345 अर्पण 346 अर्पण 347 अर्पण 348 अर्पण 349 अर्पण 350 अर्पण 351 अर्पण 352 अर्पण 353 अर्पण 354 अर्पण 355 अर्पण 356 अर्पण 357 अर्पण 358 अर्पण 359 अर्पण 360 अर्पण 361 अर्पण 362 अर्पण 363 अर्पण 364 अर्पण 365 अर्पण 366 अर्पण 367 अर्पण 368 अर्पण 369 अर्पण 370 अर्पण 371 अर्पण 372 अर्पण 373 अर्पण 374 अर्पण 375 अर्पण 376 अर्पण 377 अर्पण 378 अर्पण 379 अर्पण 380 अर्पण 381 अर्पण 382 अर्पण 383 अर्पण 384 अर्पण 385 अर्पण 386 अर्पण 387 अर्पण 388 अर्पण 389 अर्पण 390 अर्पण 391 अर्पण 392 अर्पण 393 अर्पण 394 अर्पण 395 अर्पण 396 अर्पण 397 अर्पण 398 अर्पण 399 अर्पण 400 अर्पण 401 अर्पण 402 अर्पण 403 अर्पण 404 अर्पण 405 अर्पण 406 अर्पण 407 अर्पण 408 अर्पण 409 अर्पण 410 अर्पण 411 अर्पण 412 अर्पण 413 अर्पण 414 अर्पण 415 अर्पण 416 अर्पण 417 अर्पण 418 अर्पण 419 अर्पण 420 अर्पण 421 अर्पण 422 अर्पण 423 अर्पण 424 अर्पण 425 अर्पण 426 अर्पण 427 अर्पण 428 अर्पण 429 अर्पण 430 अर्पण 431 अर्पण 432 अर्पण 433 अर्पण 434 अर्पण 435 अर्पण 436 अर्पण 437 अर्प

देवली में एसडीएम ने अपने आवासीय परिसर में लगे हरे-भरे वृक्ष कटवाये

मौके पर मजदूर ने बताया कि उपखंड अधिकारी के आदेश पर हरे वृक्षों की कटाई की जा रही है

देवली, (निर्स)। जहां हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश सहित जिलेभर में वृक्ष प्रेमियों द्वारा और सरकार की ओर से आए दिन पौधारोपण किया जा रहा है, वहीं देवली उपखंड अधिकारी और अधिशासी अधिकारी ने प्रतिबंधित हरे-भरे वृक्षों की बलि ले ली। एक और तो राज्य की भजनलाल सरकार पौधारोपण के साथ-साथ पौधों को वृक्ष बनाने तक के लक्ष्य का संकल्प दिलाव रही है, तो वहीं दूसरी ओर भजनलाल सरकार के ही अधिकारी फल-फूल रहे हरे-भरे वृक्षों को कटवाने की हटधर्मिता अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पौधारोपण करवाने जाने के लिए सरकारी एजेंसियों को लाखों के बजट के साथ पौधारोपण कार्यक्रम करवाकर सफल बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो वहीं इस कार्यक्रम में शामिल आमजन सहित वृक्ष प्रेमियों को इससे प्रेरणा मिलती है। वहीं यह भी बताया जाता है कि वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध दुरुस्त बनाए रखने में कितने महत्वपूर्ण और कितने जरूरी है। परंतु यहाँ नीम, सफेदा और अन्य वृक्षों और पौधों को कटवाया जा रहा है।

देवली उपखंड अधिकारी रूबी अंसार ने अपने आवासीय परिसर में लगे हरे घने वृक्ष नीम, सफेदा इत्यादि



देवली उपखंड अधिकारी आवासीय परिसर में लगे नीम, सफेदा के वृक्ष काट दिये।

किस्म के वृक्षों और पौधों को नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के सहयोग से पूरी तरह कटवा दिया यह मामला प्रकाश में आने के बाद जब उपखंड अधिकारी रूबी अनुसार को मीडिया द्वारा यह जानने के लिए फोन किया गया कि उपखंड अधिकारी आवास परिसर बगीचे के हरे-भरे वृक्षों को किस कारण से कटवाया जा रहा है तो इस पर उपखंड अधिकारी ने मीडिया का फोन बार-बार काट कर अड़िग रहते हुए अपनी हटधर्मिता दर्शा दी और परिसर के बगीचे के वृक्ष कटते

चले गए। इस दौरान हरे वृक्षों को काटने वाले मजदूर से जानकारी चाही कि यह हरे वृक्ष क्यों और किसके आदेश पर काटे जा रहे हैं, तो मजदूर महावीर प्रसाद माली ने जानकारी दी कि उपखंड अधिकारी के आदेश पर हरे वृक्षों की कटाई की जा रही है। इसके लिए देवली नगर पालिका ने मजदूरी पर उसे यह कार्य करने के लिए कहा है। मामला यह भी सामने आया कि जिन हरे वृक्षों की कटाई की गई उनके भारी भरकम तनों (लकड़ियों) को मशीनों से काटा गया है। इतना ही

नहीं इस मामले में पालिका के अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा प्रतिबंधित हरे-भरे वृक्षों की कटाई के मामले पर विशालकाय वृक्षों को काटने की वजह बताते पर अलग-अलग बात कह कर गुमराह करते रहे। उल्लेखनीय है कि गत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान का शुभारंभ किया था। एक और तो राजस्थान की भजनलाल सरकार ने माँ के नाम एक पेड़ लगाने की योजना पर प्रदेशभर में करोड़ों की

■ पालिका के अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा प्रतिबंधित हरे-भरे वृक्षों की कटाई के मामले पर गुमराह करते रहे

तादाद में पौधारोपण करवाते हुए प्रधानमंत्री की इस योजना को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों भी इस कार्यक्रम के तहत पौधा लगाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन उपखंड अधिकारी आवास परिसर के बगीचे में काटे गए वृक्षों के मामले में किसी भी नेता या उच्च अधिकारी ने वृक्षों की कटाई को रोकने तक का प्रयास नहीं किया, और हरे भरे प्रतिबंध वृक्ष उपखंड अधिकारी की हटधर्मिता पर कटते चले गए।

सुरेश कुमार मीणा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका देवली टोंक का कहना है कि उपखंड अधिकारी परिसर के बगीचे में लगे हरे वृक्षों की छंगाई के लिए नगर पालिका की ओर से मजदूर लगाए गए हैं। मजदूरों ने हर वृक्षों को पूरी तरह काट दिया, इस मामले का पता करवाता हूं।

25 लाख की अवैध शराब पकड़ी, दो गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निर्स)। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने लगातार दूसरे दिन गुजरात शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए की शराब की खेप पकड़ी है। पुलिस ने शराब

■ ट्रक के भीतर बनाये गये गुप्त चैबर में शराब भरी मिली

से भरे ट्रक के साथ दो तस्क़र भी गिरफ्तार किए हैं।

जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि बीती रात मुखबि़र से सूचना मिली थी कि शराब से भरा ट्रक उदयपुर की तरफ से गुजरात जा रहा है। सूचना पर बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी के नेतृत्व में रतनपुर गुजरात सीमा पर नाकेबंदी की गई। नाकेबंदी के दौरान चौकी प्रभारी गोविंदसिंह ने हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन नंबर वाले एक ट्रक को रोककर तलाशी ली। ट्रक में बायो मास



बिछीवाड़ा पुलिस ने हरियाणा निर्मित अवैध शराब समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

ब्रिक भरा हुआ था। वहीं ट्रक के भीतर गुप्त चैबर बनाकर शराब भरी हुई पाई गई। ट्रक चालक से शराब संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर वो कोई जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने हिसार हरियाणा

निवासी ट्रक ड्राइवर वीरसिंह और उसके सहयोगी वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ट्रक से शराब को उतरावाकर गिनती की तो ट्रक में 25 लाख रुपए की 386 पेटी अंग्रेजी शराब

की पेटियां भरी हुई थी, जो हरियाणा निर्मित थी। पुलिस ने ट्रक सहित अवैध शराब को जप्त कर लिया है। वहीं आबकारी अधिनियम में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

39 टीचर्स के डेपुटेशन रह किये

बीकानेर, (निर्स)। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के कुल 39 टीचर्स के डेपुटेशन रह कर दिए हैं। ये टीचर्स वेतन तो शिक्षा विभाग से ले रहे थे, लेकिन काम दूसरे विभाग में कर रहे थे। 39 में से 37 टीचर्स तो अलग-अलग जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के ऑफिस में ही वर्ष से जमे हुए थे। वहीं भरतपुर और कोटा कलेक्टर ऑफिस में डेरा डाले दो अध्यापकों को भी वापस विभाग में तलब कर लिया गया है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने राज्य सरकार के एक

■ 39 में से 37 टीचर्स तो अलग-अलग जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के ऑफिस में लगे हुये थे

आदेश की पालना में डेपुटेशन रह किए हैं। राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का ऑफिस है। इसी ऑफिस में कहीं सीनियर टीचर तो कहीं ग्रेड सैकेंड के टीचर डेपुटेशन पर चल

रहे हैं। अर अल्पसंख्यक मामला विभाग मद्रदासा बोर्ड जयपुर और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालयों में बैठे सभी टीचर्स को हटा दिया गया है। कुछ शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) भी खेल मैदान के बजाय इन ऑफिस में काम कर रहे थे। अब इन सभी को यहां से हटाया गया है। कोटा और भरतपुर के जिला कार्यालय में कार्यरत दो टीचर्स की प्रतिनियुक्ति भी निरस्त कर दी गई है। इन सभी को कार्यमुक्त करने के बाद संबंधित जिले के संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए कार्यमुक्त करना होगा।

छह गिरफ्तार

उदयपुर, (निर्स)। अवैध गांजा तस्करी के मामले में फरार छह आरोपियों को घंटाघर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर घंटाघर थानाधिकारी सुनिल शर्मा के नेतृत्व में गठित दल ने गांजा खरीद फरोख्त मामले में फरार आरोपी कमल उर्फ गोल्, विजय उर्फ दादु पुत्र खेमराज, लक्ष्मराज सिंह उर्फ भरत पुत्र विजय सिंह, भावेश पुत्र ललित, सुनील उर्फ टेणी पुत्र गणेश निवासी एकलव्य कॉलोनी अन्गामाता, रामनाथ पुत्र चंदूनाथ निवासी जेकडा वाघपुरा हाल धामगण्डी को गिरफ्तार किया है।

खेतों पर लगी विद्युत केबल चोरी

भीलवाड़ा, (निर्स)। जिले के मांडल थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं से आमजन में भय दिखाई दे रहा है। वहीं पीड़ित परिवारों में रोष है। मंगलवार रात को चौर क्षेत्र के भीमड़ियास गांव में आधा दर्जन से अधिक खेतों पर लगे विद्युत केबल को काटकर फरार हो गए। सुबह जब किसान खेत पर पहुंचे तो किसानों के खेतों पर लगी टचयूबवेल की केबल और कुओं पर लगी विपुल केबल कटी हुई मिली। इस पर अन्य ग्रामीणों को घटना के बारे में अवगत कराय़ा। सभी ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पहले भी कई बार चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। लगातार चोरी की घटनाओं के कारण लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। पीड़ितों में गांव के ही गोपाल बलाई, पनालाल बलाई, शंकलाल बलाई, सोहन बलाई, कैलाश कामड, भैरू लोहार सहित कई किसानों के यहां पर खेतों में चोरी की घटनाएं हुई हैं।

डीडवाना-कुचामन में सड़क हादसे रोकने के लिये “सेफ आई-सेफ हाइवे” अभियान शुरू

सड़क हादसों को रोकने की दिशा में एक अनोखा और सराहनीय कदम उठाया, हादसों पर लगाम लगेगी

डीडवाना, (निर्स)। कुचामन जिले में सड़क हादसों को रोकने की दिशा में एक अनोखा और सराहनीय कदम उठाया गया है। जिले में पहली बार “सेफ आई-सेफ हाइवे” अभियान की शुरुआत हुई है, जिसका शुभारंभ छापरी-दौलतपुरा टोल प्लाजा से राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने किया। इस मौके पर मंत्री चौधरी ने अभियान को सड़क हादसों में कमी लाने वाला प्रयास बताया और कहा कि यह केवल स्वास्थ्य शिविर नहीं, बल्कि जनजीवन को बचाने का मिशन है, जिसे वे पूरे प्रदेश में लागू करवाने के लिए सरकार से चर्चा करेंगे।

इस अभियान के तहत टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के चालकों, खासकर ट्रकों के चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चालकों की आंखों की रोशनी, बीपी, शुगर और बीएमआई की जांच की गई और जिनकी नजर कमजोर पाई गई, उन्हें मौके पर ही निःशुल्क चश्मे दिए गए। ब्लड प्रेशर या शुगर की समस्या सामने आने पर उन्हें



अभियान के तहत टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों की जांच कर निःशुल्क चश्मे दिए।

फौरन दवाईयां और परामर्श भी दिया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड्गावत ने बताया कि अभियान के पहले ही दिन 300 से ज्यादा चालकों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिनमें से कई

को चश्मे और दवाईयां दी गईं। उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न टोल प्लाजा पर अब हर महीने तीन शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें चिकित्सा, पुलिस और परिवहन विभाग को संयुक्त भागीदारी

रहेगी। उनका कहना है कि इस अभियान के जरिए, सड़क हादसों में 25 प्रतिशत तक की कमी लाई जा सकती है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने भी अभियान को सड़क

■ यह अभियान केवल स्वास्थ्य शिविर नहीं, बल्कि जनजीवन को बचाने का मिशन है, जिसे पूरे प्रदेश में लागू करवाने के लिए सरकार से चर्चा करेंगे : राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी

■ अभियान का शुभारंभ छापरी-दौलतपुरा टोल प्लाजा से राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने किया

सुरक्षा की बड़ी पहल बताया। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस और प्रशासन सड़क हादसों को रोकने के लिए एक विस्तृत योजना पर काम कर रहे हैं, जिसमें ब्लैक स्मॉट सुधारने, अन्य कमियां दूर करने और ऐसे स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन भी शामिल है।

स्वास्थ्य परीक्षण करवाने पहुंचे ट्रक चालक भी इस पहल से बेहद संतुष्ट नजर आए। पंजनाब के हरजिंदर सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य के चलते वह कभी अपना स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवा पाते थे, लेकिन इस शिविर में उन्हें पता चला कि उनका बीपी हाई है और नजर

जर्जर स्कूल भवन की छत ढही

उदयपुर, (निर्स)। जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाके कोटड़ा के महाड़ी बंवरिया फला सांकरा की उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत बुधवार को अचानक ढह गई। हादसा सुबह छह बजे हुआ उस समय स्कूल में शिक्षक और छात्र कोई भी नहीं थे इस कारण कोई नुक़ान नहीं हुआ। सूचना पर उपखण्ड अधिकारी हंसमुख कुमार मौके पर पहुंचे और जेसीबी कीमदद से मलबा हटवाकर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पास स्थित दूसरे भवन में स्कूल का संचालन शुरू करवाया। शिक्षकों के अनुसार गत दो वर्षों से भवन की हालत खस्ता है, जिसकी सूचना उच्चस्थ वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे चुके हैं। शिक्षक अरविन्द के अनुसार स्कूल भवन की जर्जर हालत के कारण नामांकन 225 से घटकर 190 हो गया है। यह स्कूल 2021-22 में क्रमोन्नत हुआ तब से अतिरिक्त कमरे की भी मांग कर रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं होने से जर्जर भवन में बने दो कक्ष में ही स्कूल चलाना पड़ रहा है।

कुराबड ब्लॉक में लैपर्ड का आतंक

उदयपुर, (निर्स)। जिले के कुराबड ब्लॉक में आतंक का पर्याय बने लेपर्ड ने मंगलवार रात में दो अलग-अलग गांवों में तीन श्वानों को अपना शिकार कर ग्रामीणों को और भयभीत कर दिया है। पहली घटना ग्राम पंचायत गुडली के काली मगरी गांव की है। जहां ग्रामीण भेरूनाथ के घर के बाहर बैठे पालतू श्वान को लेपर्ड ने अपना शिकार बना लिया। दूसरी घटना बोरी ग्राम पंचायत के आछट गांव की है जहां लेपर्ड ने दो श्वानों को अपना निवाला बना लिया। श्वानों के विल्लाने की आवासज सुन कर ग्रामीणों ने जाकर देखा तो लेपर्ड तेजी से भागता दिखा।

कार्यालय नगर पालिका, इन्द्रगढ़ जिला बुन्दी (राज.)

क्रमांक : न.पा.ई. / 2025-26 / 1778दिनांक : 04.08.2025

NOTICE INVITING BIDS

Bid for Nagar Palika Indragarh of Procurement are Invited from Interested Bidders Up to 11.00 AM , 04.08.2025 To 20.08.2025. Other particulars of the Bid Army be Visited on the Procurement Portal (<http://sppp.raj.nic.in>) or (www.gem.gov.in) of the State, and local self Departmental Website.

NIB Code :- DLB2526A4329

UBN :- 1. DLB2526SLRC13716

2. DLB2526SLRC13717

अध्यक्ष

नगर पालिका इन्द्रगढ़

राज.संवाद / सी / 25 / 7666

अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका इन्द्रगढ़

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DN GHATOL DISTT BANSWARA (RAJ.)

No. 312Date: 25.07.2025

Notice Inviting Bid No. 02/2025-26

NIB- PWD2526A2221

Bids for Rate Contract of Road Repair and Maintenance Works are invited from interested bidder's upto 19.08.2025, 05.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://www.eproc.rajjasthan.gov.in> and <http://www.sppp.rajjasthan.gov.in>) of the state. The approximate value of procurement is rs. 215.00 Lacs.

UBN- PWD2526WSOB08033, TO PWD2526WSOB08038

(Naresh Shersya)

Executive Engineer

PWD Division Ghatol

Distt. Banswara

DIPRC/10830/2025

MBM UNIVERSITY, JODHPUR

Advertisement No. :- MBMU/DFPEA/ADVT/2025/15Dated :- 31/07/2025

Admission Notice - 2025-2026

Ph. D, P.G., B. Plan and ADCGC Course

Applications are invited from eligible candidates for admission Ph. D, P.G., B. Plan and Advance Diploma in Child Guidance and Counselling Course in MBM University, Jodhpur. Interested candidates should apply online on the MBM University website on or before 11 August, 2025, and deposit the application fee online. It is essential to submit the hard copy of their application forms along with proof of application fee and all requisite documents on or before 05:00 PM, 18 August 2025 in the respective Department of the MBM University, Jodhpur (Raj.). All further information will be given only on the University website <https://mbm.ac.in>, admission.mbmunioms.in.

Raj.Samwad/C/25/7616

Registrar, MBM University, Jodhpur

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

RAJASTHAN STATE HIGHWAYS AUTHORITY, JAIPUR

No.Raj.Kaj No. 16935834Date: 04.08.2025

NIT NO. 23/2025-26

NOTICE INVITING BID

Bids for "Routing maintenance of Ajeetgarh-Chala section of SH-13, Sikar-Ganeri Jaisangwarh section of SH-20 & 20A, Bidasar-Nakha section of SH-20 and Singhana-Buhana-Haryabhar border section of SH-133 (total length: 233.955 Km.) are invited from interested bidders upto 11.30 AM (10.08.2025). The date of opening of bids if 11.08.2025 at 12.00 PM.

Other particulars of bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.rajjasthan.gov.in>, <https://sppp.rajjasthan.gov.in>) of the state. The estimated value of aforementioned work is Rs. 192.60 Lakh.

UBN NO. PWD2526WSOB0825

(Akshay Kumar Jain)

Member (C & PPP),

RSHA, Jaipur

DIPRC/11067/2025

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर

111, वल्लभ नगर, उदयपुर (राज.) फ़ोन 313001 दूरभाष 0294-241571, E-mail: directorrcert@rajasthan.gov.in

क्रमांक - सर्वोच्च अग्र-उच्च/उच्च/2025-26/1173दिनांक - 05/08/2025

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि RSCERT, उदयपुर द्वारा अनुपयोगी / अग्र चलित / नकारा सामग्री जिनकी Book Value IT Equipments/Electronics Rs. 3017786 एवं Non IT Equipments - Furniture etc. Rs. 175964 है की सार्वजनिक नीलामी जहाँ है जैसी स्थिति में है उस आधार पर दिनांक 29.08.2025 को प्रातः 11.30 बजे से कार्यालय के परिसर में की जावेगी। नीलामी योग्य सामग्री का अवलोकन एवं नीलामी की अन्य शर्तें कार्यालय समय में कार्यालय में देखी जा सकती है।

निदेशक

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर

रज.संवाद/सी/75/7662

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

Tel No. 1462-258665, 257509Email Add: npsbawar@gmail.com

क्रमांक / निर्माण / 2025-26 / 5958दिनांक- 04.08.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 08/2025-26

नगर परिषद, ब्यावर द्वारा परिषद क्षेत्र में SFC, FFC एवं परिषद कोष के अन्तर्गत निम्नांकित निर्माण कार्य करवाया जाने हेतु परिषद के सम्बन्धित श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारी एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के पंजीकृत ठेकेदारी से E-Procurement प्रक्रिया के तहत केवल www.eproc.rajjasthan.gov.in की ऑनलाईन निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 20/08/2025 सायं 06:00 बजे तक निविदा भरी जा सकती है एवं ई-निविदा फॉर्म शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस की राशि नगर परिषद के Axis Bank के खाता संख्या 914010005810609 आई.एफ.सी. कोड UTIB0001825 में जमा कराकर बोली धरोहर का डी. डी./बैंकर चेक नगर परिषद, ब्यावर के निर्माण शाखा में दिनांक 21/08/2025 को प्रातः 11 बजे से पूर्व जमा कराना अनिवार्य कराना अनिवार्य है। कुल 04 निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 31.67 लाख रुपये है। ई-निविदा सूचना की समस्त शर्तें SPPPP पोर्टल पर देखी जा सकती है।

जिसका NIB Code DLB2526A4329 है एवं UBN नम्बर निम्नानुसार है:-

(i) DLB2526WSOB13676 (ii) DLB2526WSOB13678 (iii) DLB2526WSOB13680 (iv) DLB2526WSOB13681

आयुक्त

प्रशासक

राज.संवाद / सी / 25 / 7652

नगर परिषद, ब्यावर

नगर परिषद, ब्यावर

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद

(राज्यीय) विश्व प्रतिरोधक प्रबंधन प्रणाली, कोटा, Website : www.kotamc.org, Email : nksouth@gmail.com

क्रमांक - प. 4(1)टीपीएनए/संसाधन/2025/287दिनांक - 28/05/2025

संशोधित बिड सूचना

इस कार्यालय द्वारा जारी बिड सूचना संख्या-240 दिनांक 18.07.2025 UBN No.- RGA2526SLRC00114 में बिड प्रपत्र की Technical Bid Data Sheet के बिन्दु संख्या-6 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

1. A Self Declaration for not being black listed by any Procuring entity if Debarred by the State Government and Rajasthan Gramin Ajivika vikas Parishad. Department During the last 3 years with seal & Sign of Authorised Signatory.

उक्त के अतिरिक्त बिड प्रस्तुत करने, कार्यालय में डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने एवं बिड खोलने की दिनांक भी निम्नानुसार संशोधित की जाती है :-

क्र. सं.	Activity	निविदा दिनांक	समय
1	Last Date & Time for Submission for Bid	13.08.2025	11:30 AM
2	Last Date & Time for Submit Physical Demand Draft (DD)	13.08.2025	12:00 PM
3	Date & Time of Technical Bid Opening	13.08.2025	12:30 PM

रज.संवाद/सी/25/7643

जिला परिोजना प्रबंधक, राजीविका, जयपुर

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

राजीव गांधी श्रम, रक्षा और न्याय, कोटा, Website : www.kotamc.org, Email : nksouth@gmail.com

क्रमांक - न.निका/रक्षा/निगम/2025/567-581दिनांक - 29/07/2025

Notice inviting request for proposal (RFP) : 2025-26

नगर निगम कोटा दक्षिण की ओर से नगर निगम कोटा दक्षिण में कन्सलटेन्ट/पेनल के गठन हेतु कुल निम्न कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। संवेदक निविदा प्रपत्र नगर निगम कोटा दक्षिण की वेबसाइट <http://kotamcsouth.org.com>, <http://www.urban.rajjasthan.gov.in/anks>, <http://sppp.raj.nic.in>, <http://eproc.rajjasthan.gov.in>, से प्राप्त कर सकेंगे।

निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाइट से) : 01.08.2025 से 14.08.2025 तक

निविदा की धरोहर राशि, निविदा शुल्क व प्रोसेसिंग शुल्क व तकनीकी बिड के दस्तावेज ऑन-लाईन अपलोड करने की तिथि : 07.08.2025 (प्रातः 11:00 बजे)

प्री-बिड मीटिंग की तिथि (अधीक्षण अनिवार्य कक्ष) : 18.08.2025 (प्रातः 11:00 बजे)

निविदा खोलने की तिथि

क्र. सं.	कार्य का नाम	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	फीस	समयावधि
1	Preparation of DPR & BoQ including architecture and structural and design services with details planning. (i) Commercial Complex/ Other Building/ Facad Development/ Parks/ Land Scapina/ Beautification Projects.	25000/-	1500/-	500/-	12 माह
2	Preparation of DPR & BoQ including architecture and structural and design services with details planning. (ii) Chouraha Geo-Metrical Desig/ Sports Grounds/ Roads/ Small Bridge.	25000/-	1500/-	500/-	12 माह
3	Preparation of DPR & BoQ including architecture and structural and design services with details planning. (i) Community/ Shamsaahn/ Toilets	25000/-	1500/-	500/-	12 माह
4	Preparation of 3D Model of proposed schemes/ Building/ Chauraha etc. (ii) Computer Generated Model/ 3D View (All Sides)/ Walk Through.	25000/-	1500/-	500/-	12 माह

रज.संवाद/सी/25/7678

अधीक्षण अधिकारी

नगर निगम कोटा दक्षिण

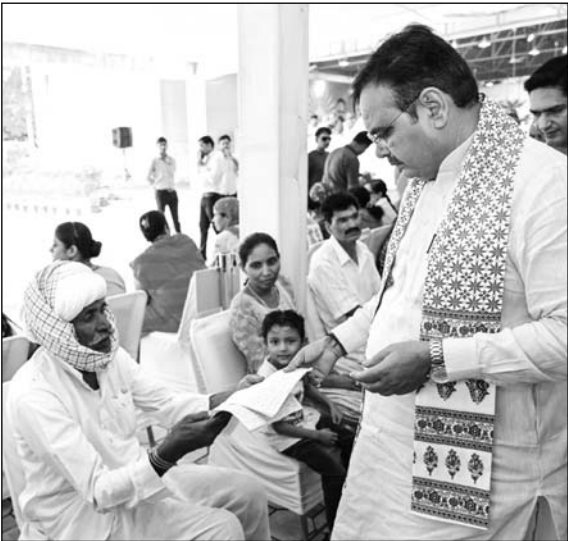
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से जनसुनवाई बनी सुशासन की नई मिसाल

मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते हुए इन सभी प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन की प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। शासन की सेवा का माध्यम मानते हुए यह सरकार

- जयराम और कैलाश को मिला कृषि विद्युत कनेक्शन**
- मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद, अब नहीं सूख रही फसलें**

प्रदेशवासियों के हित के लिए पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं संवेदनशीलता के साथ पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा नियमित रूप से की जा रही जनसुनवाई भी इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सार्थक कदम है।



मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई में समस्या का समाधान किया।

जनसुनवाई में फरियादी नगर निगम, जेडीए, गृह, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,

जल संसाधन सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। कोई परिवारी बीमारी में इलाज की मदद के लिए आते हैं तो कोई परिवारी अपनी पेंशन से जुड़े प्रकरण

को निस्तारण के लिए तो कोई विद्युत कृषि कनेक्शन के लिए। मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते हुए इन सभी प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर रहे हैं जिससे आमजन में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।

कोटपूतली के नारायणपुर तहसील निवासी जयराम किसान परिवार से हैं। उन्होंने कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया था जोकि पिछले काफी समय से लंबित था। जनसुनवाई में अपने इस प्रकरण को लेकर जब जयराम आए तो मुख्यमंत्री ने फसलों के सीजन को देखते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। अधिकारियों ने जयराम के कृषि कनेक्शन आवेदन को प्राथमिकता से लेते हुए कनेक्शन उपलब्ध करा दिया। इसी तरह अलवर की लक्ष्मणगढ़ तहसील के कैलाश चंद मीणा को भी कृषि विद्युत कनेक्शन के अभाव में फसलों की सिंचाई नहीं होने से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने जनसुनवाई में मुख्यमंत्री को अपनी इस परेशानी से अवगत कराया।

कुमावत को एड-हॉक कमेटी का कंवीनर बनाने पर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड-हॉक कमेटी के क-वीनर के तौर पर दीनदयाल कुमावत की नियुक्ति करने पर सहकारिता रजिस्ट्रार, आरसीए और दीनदयाल कुमावत को नोटिस जारी कर 19 अगस्त तक जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सवार माधोपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक

27 जून को दीनदयाल कुमावत को आरसीए की एड-हॉक कमेटी का क-वीनर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। एड-हॉक कमेटी का कंवीनर वह व्यक्ति ही बन सकता है, जो आरसीए चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो। दीन दयाल कुमावत का सवाई माधोपुर से कोई रिश्ता ही नहीं है। वे ना तो सवाई माधोपुर में जन्मे और ना ही वहां निवास करते हैं। वे सवाई माधोपुर

के किसी प्राइमरी क्रिकेट क्लब के पदाधिकारी भी नहीं है। ऐसे में वे जिला संघ के किसी पद के लिए भी पात्र नहीं हैं। इसके बावजूद भी उन्हें एड-हॉक कमेटी का कंवीनर बनाया गया है। इसलिए उनके नियुक्ति आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों और दीनदयाल कुमावत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

भारतीय नागरिकों के विदेश में जन्मे बच्चों के हितों को सुरक्षित करे सरकार

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को कहा है कि वह भारतीय नागरिकों के विदेश में जन्मे बच्चों के हितों को सुरक्षित करने के लिए कानून की समीक्षा करे और जरूरत पड़ने पर उन्हें संशोधित करने पर विचार करे। अदालत ने कहा कि ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे को मजबूत करने और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ऐसे अनूठी परिस्थिति में बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो सके। जस्टिस अनूप कुमार डंड की एकलपीठ ने यह आदेश सेहर गंगिया के अपने पिता के जरिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि इमिग्रेशन ब्यूरो याचिकाकर्ता की मां की एनओसी के बिना उसकी वीजा अवधि अधिकतम समय के लिए बढ़ाई। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता ब्यूरो में ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन करे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पांच साल की बच्ची है और उसे ऑस्ट्रेलिया निवासित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

याचिका में कहा गया कि उसके माता-पिता का मार्च, 2018 में विवाह हुआ था। इसके बाद वे आस्ट्रेलिया गए थे। जहां 1 जून, 2020 को याचिकाकर्ता का जन्म हुआ। इस पर वहां की सरकार ने नवंबर, 2021 में

- अदालत ने कहा कि इमिग्रेशन ब्यूरो याचिकाकर्ता की मां की एनओसी के बिना उसकी वीजा अवधि अधिकतम समय के लिए बढ़ाई। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता ब्यूरो में ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन करे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पांच साल की बच्ची है और उसे ऑस्ट्रेलिया निवासित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता**
- याचिकाकर्ता पांच साल की बच्ची है और उसे ऑस्ट्रेलिया निवासित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता**

याचिकाकर्ता को नागरिकता दे दी। इसके बाद वह भारत सरकार से वीजा लेकर अपने माता-पिता के साथ यहां आ गईं। इस दौरान उसकी समय-समय पर वीजा अवधि 24 जनवरी, 2024 तक बढ़ाई गई। याचिका में कहा गया कि इस बीच याचिकाकर्ता के माता-पिता के बीच वैवाहिक विवाद पैदा हो गया और उसकी मां ने याचिकाकर्ता के पिता पर कई केस कर दिए। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से इमिग्रेशन ब्यूरो में याचिकाकर्ता की वीजा अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया, जिसे ब्यूरो ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसकी मां ने वीजा अवधि बढ़ाने के लिए एनओसी नहीं दी। ऐसे में याचिकाकर्ता को आशंका है कि उसे अवैध प्रवासी मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई की

जाएगी। इसलिए मामले में कोर्ट दखल देकर उसकी वीजा अवधि बढ़ाए। इसका विरोध करते हुए इमिग्रेशन ब्यूरो की ओर से अभी तक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया गया है। हालांकि इसके बावजूद भी विभाग याचिकाकर्ता के खिलाफ कई दंडात्मक कार्रवाई या उसे डिपोर्ट नहीं कर रहा है। ब्यूरो की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ऑस्ट्रेलिया के नागरिक है और उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए याचिका को खारिज किया जाए।

शिक्षा के साथ संस्कारों की सीख दे रहा है गायत्री परिवार: दिलावर

जयपुर। किरण पथ, मानसरोवर स्थित गायत्री वेदना निवारण केंद्र परिसर में मां भगवती उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रवेशोत्सव- 2025 बुधवार को मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर थे। उन्होंने मां गायत्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर दिलावर ने कहा कि गायत्री परिवार के इस विद्यालय ने बहुत कम समय में अच्छी तरक्की की है। यह विद्यालय शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार भी प्रदान कर रहा है। यह बहुत खुशी की बात है कि विद्यालय का शुभारंभ मेरे द्वारा हुआ था तथा आज प्रवेश उत्सव भी मेरी उपस्थिति में हो रहा है। विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षकों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार सामाजिक एवं राष्ट्रहित के कामों में सदा अग्रणी रहता है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि गायत्री परिवार सदैव समाज एवं राष्ट्र के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राजकीय विद्यालय में बड़ी तेजी से नामांकन व वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए गुणात्मक प्रयास एवं नवाचारों का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है। बच्चों ने गायत्री मंत्र के उच्चारण के



गायत्री परिवार के मां भगवती विद्यालय के नव प्रवेशित छात्रों का प्रवेश उत्सव मनाया।

साथ शिक्षा मंत्री का आत्मीय स्वागत किया। शिक्षा मंत्री एवं अन्य अतिथियों ने बच्चों को स्कूल बैग, स्टेशनरी सहित अन्य आवश्यक सामग्री भी वितरित की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए गायत्री परिवार के मुख्य ट्रस्टी एवं राजस्थान जोन समन्वयक ओमप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि यह विद्यालय गायत्री परिवार द्वारा नि:शुल्क संचालित किया जा रहा है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय में

नवोदय विद्यालयों में सुरक्षा व स्टाफिंग में खामियों को लेकर नोटिस जारी

आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच 147 छात्रों ने आत्महत्या की थी

जयपुर/जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पी.एस. भाटी और न्यायमूर्ति संदीप तनेजा शामिल हैं, ने देशभर के जवाहर नवोदय विद्यालयों में सुरक्षा, स्टाफिंग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर खामियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार,

शिक्षा मंत्रालय और नवोदय विद्यालय समिति को नोटिस जारी किया है। यह याचिका अधिवक्ता विनीत आर. दवे द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कई नवोदय विद्यालयों में अब तक पूर्णकालिक वार्डन, काउंसलर, सीसीटीवी निगरानी, परिधि सुरक्षा, आपात प्रबंधन और शिकायत निवारण तंत्र जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं। जबकि शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई, एनसीपीसीआर, एनडीएमए द्वारा इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कई चौंकाने वाले तथ्य को उजागर

- जवाहर नवोदय विद्यालय में 6800 से भी अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं**
- विद्यालयों में साफ सफाई, सुरक्षा, टुटे-फुटे आधारभूत ढांचे और अन्य कई तरह की मानसिक परेशानीयो से छात्रों को झुझना पड़ता है**

किया है जैसे कि दिसम्बर 2024 की देखरेख के लिए नियुक्त करने का निर्देश दिया गया, जो केवल औपचारिकता रह गया है और योग्यता आधारित स्टाफिंग के मापदंडों का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त, याचिका में यह भी जोर दिया गया है कि विगत वर्षों में नवोदय विद्यालयों में आत्महत्याओं सहित कई छात्र मौतों की घटनाएं सामने आई हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी और छात्रवासों में अपर्याप्त निगरानी की ओर इशारा करती हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि आरटीआई से प्राप्त जानकारी के

अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच 147 छात्रों ने आत्महत्या की थी। आरटीआई से ही प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 से 2017 के बिच ही इन विद्यालयों में 49 छात्रों ने आत्महत्या की, जिसमें से आधे एसएसी -एसटी वर्ग के थे। वही 2019 से 2023 के बीच 25 छात्रों ने आत्महत्या की, जिसमें भी एक बड़ा हिस्सा एसएसी -एसटी वर्ग का था। याचिकाकर्ता का कहना है कि ज्यादातर इन मौतों में कई मामलों में एफआईआर दर्ज है परन्तु कई मामलों में मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि इन विद्यालयों में साफ सफाई, सुरक्षा, टुटे-फुटे आधारभूत ढांचे और अन्य कई तरह की मानसिक परेशानीयो से छात्रों को झुझना पड़ता है, और आये दिन इन मुद्दों पर प्रदर्शन किये जाते हैं। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं।

विवाद बढ़ा तो ठेकेदारों ने 20 प्रतिशत रेट घटाकर ले लिया पौधे सप्लाई का टैंडर

- कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। ग्रेटर निगम में पौधे सप्लाई के टैंडर में भारी गड़बड़झाला चल रहा है। "वन टाइम प्लान्टेशन" के लिए 10 फ़ीट पौधे देने के लिए ठेकेदारों ने पहले तो मात्र 5 प्रतिशत कम रेट डाली थी, परन्तु हैरिटेज निगम में 55 प्रतिशत कम दर आने के बाद जब विवाद बढ़ा तो इन्हीं फर्मों ने अपनी रेट 20 प्रतिशत तक घटाकर काम ले लिया।

अब चर्चाएं यह हो रही हैं कि आखिर हैरिटेज निगम से 35 फ़ीसदी ज्यादा कीमत पर पौधे खरीदने के लिए ग्रेटर निगम के अफसर उत्सुक क्यों हैं? वह भी उस स्थिति में जब अधिकांश ठेके एक ही फर्म मैसर्स जसवाल बिल्डर्स के नाम पर छूटे हैं। हालाँकि उद्यान शाखा के अफसरों का कहना है कि 50 से 55 प्रतिशत कम राशि पर पौधे उपलब्ध

करवाना संभव ही नहीं है। परन्तु सवाल यह उठ रहा है कि यह चिंता तो कम दर पर ठेके लेने वाले संवेदक को होनी चाहिए।

सूत्रों के मुताबिक ग्रेटर निगम प्रशासन ने वन टाइम प्लान्टेशन कि निविदा के कार्यदिश "नेगोशिएशन" के बाद 20 प्रतिशत कम दर पर जारी किये हैं। यहाँ ठेकेदार ने 300 रुपए के 10 फीट के पेड़ 270 से 285 रुपए तक में देने की दर डाली थी, परन्तु जब हैरिटेज निगम में आधी कीमत यानी कि 135 से 150 रुपए तक की रेट आयी तो बड़ा विवाद हो गया। तमाम विवादों के बावजूद ग्रेटर निगम प्रशासन ने यह कार्यादेश जारी करने का फैसला लिया। मजदार बात यह है कि जेडीए प्रशासन ने भी 150 से 170 रुपए के पौधे खरीदे हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहे हैं कि आखिर

ग्रेटर निगम प्रशासन ही जानबूझकर लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान क्यों झेलने पर उतारू है। जबकि तीनों विभागों ने पौधों की एक समान खरीद दर 300 रुपए तय की थी। जिसमें नीम, शीशम, करंज, गुलमोहर, अमलतास, अशोक, चंपा, आवला, सीताफल, खेजड़ी, अर्जुन, बालम खेड़ा, करने, हरसिंगार, शहतूत, अमरूद, पीपल, जामुन, बेलपत्र, गुड़हल, मौलश्री, चंदन और आम के पेड़ शामिल हैं।

सूत्रों की माने तो ग्रेटर नगर निगम की उद्यान शाखा ने इस बार "वन टाइम प्लान्टेशन" के 30 लाख रुपए से कम के टैंडर में भी कुछ ऐसी शर्तें जोड़ दी थी, जिसके कारण "डी" श्रेणी के ठेकेदार चाहते हुए भी इसमें शामिल नहीं हो पाए। इस कारण इन निविदाओं में सिर्फ चुनिंदा फर्मों ने ही भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने दी भूमि आवंटन की स्वीकृति

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से 10 अगस्त को पूरे राजस्थान में विद्युत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

- जैसलमेर के फूसासर में 765 के.वी. में स्थापित होगा विद्युत उपकेन्द्र**

सरकार द्वारा बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए प्राथमिकता से निर्णय लिए जा रहे हैं।

इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने जैसलमेर जिले की भगियाणा तहसील के फूसासर में 765 के.वी. के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा यह विद्युत उपकेन्द्र 80 हैक्टेयर भूमि पर स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री का यह निर्णय पश्चिमी राजस्थान सहित पूरे प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस उपकेन्द्र की स्थापना से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा आमजन को सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

भाजपा रक्षाबंधन पर्व को सेवा, संगठन और समर्पण के रूप में मनाएगी

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी आगामी 8 से 10 अगस्त तक पूरे राजस्थान में रक्षाबंधन पर्व को जनसहभागिता, संगठनात्मक सहभागिता एवं सामाजिक समर्पण के साथ भव्य रूप में मनाने जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता "रक्षा का यह पर्व, सामाजिक एकता और सेवा का अवसर" के मूलभाव के साथ जिलों, विधानसभाओं और मंडलों में समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाएंगे।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और अभियान संयोजक मुकेश दाधीच ने बताया कि प्रत्येक जिले में एक जिला महामंत्री एवं महिला मोर्चा की दो पदाधिकारी संयोजक व सह प्रोजेक्ट के रूप में कार्यक्रम का संचालन करेंगे।

8 अगस्त को सम्मान व समर्पण दिवस:

इस दिन पार्टी कार्यकर्ता टैफिक पुलिस, अस्पताल स्टाफ, विद्यालयों, सरकारी व निजी कार्यालयों, पुलिस स्टेशनों सहित सेवाभावी कर्मियों को राखी बांधकर आभार प्रकट करेंगे। बहनों द्वारा तिलक, राखी एवं मिष्ठान वितरण कर यह संदेश दिया जाएगा— आप हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं।

स्थानीय मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से इस सेवा भावना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

9 अगस्त को संगठनात्मक एकता

व परिवार दिवस पर भाजपा कार्यकर्ता इस दिन अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाएंगे और बुध, मंडल, शक्ति केंद्र स्तर पर संगठन के सदस्यों के बीच भाईचारे का पर्व मनाकर भाजपा परिवार – एक सूत्र में बंधा, संकल्पित भारत के लिए समर्पित भाव का संशक्त करेंगे।

10 अगस्त को सेवा व सामाजिक सद्भाव दिवस को भाजपा कार्यकर्ता सीमाओं पर तैनात सैनिकों को राखी भेजेंगे या उनके साथ रक्षाबंधन मनाएंगे। साथ ही कच्ची बस्तियां, मजदूर बस्तियां, झुग्गी-झोपडियों और घुमंठू समाज के बीच जाकर राखी व मिठाई वितरित की जाएगी। यह दिन "रक्षा का धागा, सम्मान और अपनत्व का संदेश" लेकर सेवा और संवेदना का उत्सव बनेगा।

यह आयोजन सांसदों, विधायकों, जिलाध्यक्षों व अन्य पदाधिकारियों की सहभागिता से जिले, विधानसभा एवं मंडल स्तर पर आयोजित होगा। पूर्व तैयारी बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं।

भाजपा का उद्देश्य रक्षाबंधन को सेवा, संगठन और समर्पण के पर्व के रूप में जन-जन तक पहुंचाना है।

रक्षा सूत्र से बंधेगा भारत, एकता, सेवा और संस्कारों के साथ – यही है इस कार्यक्रम की मूल भावना।

जयपुर स्मार्ट सिटी सीईओ डॉ. निधि पटेल ने की समीक्षा बैठक

जयपुर। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सीईओ डॉ निधि पटेल ने बुधवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान स्मार्ट सिटी सीईओ डॉ निधि पटेल ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था की नियमित माॉनिटिंग करने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि स्मार्ट सिटी में बने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कैमरों से कचरा फैकने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए।

जिससे कि सड़क पर कचरा फैकने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीईओ निधि पटेल ने कहा कि आमतौर पर देखा जा रहा है कि शहर के प्रमुख बाजारों में देर रात तक खुलने वाली दुकानों से कचरा सड़क पर ही फैका जा रहा है, जो कि सुबह तक सड़क पर ही पड़ा रहता है और ओपन डिपो का रूप लेकर शहर में सफाई व्यवस्था को खराब कर रहा है। इसलिए एगिनिगम प्रशासन और स्मार्ट सिटी के अधिकारी मिलकर दोस प्लानिंग करें और उन दुकानों को चिह्नित कर समझाइश करें नहीं मानने पर भारी



जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सीईओ डॉ. निधि पटेल ने बुधवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में समीक्षा बैठक की।

चालान वसूला जाए। जिससे कि सफाई व्यवस्था बेहतर हो।

वहीं समीक्षा बैठक के दौरान सीईओ निधि पटेल ने स्मार्ट सिटी के प्रगतिरत प्रोजेक्ट को समीक्षा की और कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। साथ ही लाल डुंगरी कचरा ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण कार्य, एमआरएफ प्लॉट के शुरू होने के लिए शीघ्र पॉल्यूशन पुनःओसी लेने और लंगडियावास में पौधरोपण करने के निर्देश दिए।समीक्षा बैठक में स्मार्ट सिटी

के अधिकारी और नगर निगम हेरिटेज के जोन उपायुक्त और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

बाजारों में कचरा संग्रहण के लिए चल रहे निगम के हूपर, व्यापारी हूपर में ही डालें कचरा वहाँ, सीईओ डॉ निधि पटेल ने कहा कि नगर निगम हेरिटेज की ओर से समयानुकूल सभी बाजारों में हूपर चल रहे हैं। दुकानदार अपने कचरे को हूपर में ही डालें, सड़क पर कचरा नहीं फैलाएँ, जिससे कि सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो।

माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने के लिए डीपीआर बनेगी

सात हजार करोड़ रूपए की परियोजना से पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर की पेयजल समस्या का स्थाई निदान होगा

जयपुर, 6 अगस्त। पाली, जालोर, सिरोही बाड़मेर में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अब मूर्त रूप लेगा। इस विषय को लेकर सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ एक अहम बैठक हुई। बैठक में सात हजार करोड़

- मुख्यमंत्री भजनलाल, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने परियोजना के बारे में विस्तार से ब्रीफ किया।
- वाफ़ोस ने परियोजना की इन्सपैक्शन रिपोर्ट जल संसाधन संभाग को सौंपी।

रूपए के इस प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने के संबंध में चर्चा हुई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने माही एवं सोम नदी का मानसून अवधि का अधिशेष जल, जयसमंद बांध सहित अन्य बांधों को भरते हुए जवाई बांध तक लाने संबंधी कार्य की, 2024–25 के बजट में घोषणा की थी। इस



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बुधवार को सुमेरपुर विधायक व कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने एक बैठक में माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने वाले सात हजार करोड़ रूपए के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चर्चा की।

परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए 15.60 करोड़ रूपए की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति जल संसाधान विभाग, जयपुर के मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा जारी कर दी गई है। इस कार्य के लिए अधिशासी अभियंता, जल संसाधान खंड सलूंवर ने

वाफ़ोस लिमिटेड से अनुबंध कर कार्यदेश भी जारी कर दिए। इसके बाद वाफ़ोस द्वारा इन्सपेक्शन रिपोर्ट जल संसाधन संभाग, उदयपुर को प्रस्तुत किये जाने के बाद विभाग ने उसका अनुमोदन भी कर दिया है।

कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने

बताया कि सात हजार करोड़ रूपए का यह महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूरा होने पर उदयपुर, सिरोही, पाली एवं जोधपुर जिले में पेयजल संबंधी समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। इसके साथ ही, 16 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का पुर्नस्थापन होगा।

विपक्ष ने संसदीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
उन झूठे दावों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है, जो संसद को सुचारु रूप से चलने से रोक रहे हैं।”

गोगोई ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि 1961 में राज्यसभा में चुनाव आचार संहिता के नियमों में संशोधन पर बहस हुई थी, उस चर्चा का नेतृत्व उस समय के कानून मंत्री गोपाल खरोष पाठक ने किया था। गोगोई ने बताया कि 1981 में, कांग्रेस सांसद मनुभाई पटेल ने चुनावी कानूनों की समीक्षा के लिए एक संसदीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस सांसद ने कहा, “1991 में, राज्यसभा में मौजूदा चुनावी कानूनों में संशोधन की तत्काल आवश्यकता पर बहस हुई। 2015 में, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने प्रवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) के लिए

प्रॉक्सी और ई-पोस्टल वोटिंग पर “कॉलिंग अटेंशन मोशन” प्रस्तुत किया था। कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने विपक्ष की राय को मानने की बात स्वीकार की।”

गोगोई ने कहा कि हाल ही में, 2019 में भी चुनावी सुधारों पर “अल्पकालिक चर्चा” हुई थी, जिसमें तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भाग लिया था। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। सरकार को इस लंबे समय से लंबित और आवश्यक बहस में देरी नहीं करनी चाहिए।

गोगोई ने कहा, “आइए, संसद में चुनावी सुधारों पर चर्चा करें।” रमेश ने एक और उदाहरण देते हुए कहा कि 1986 में भी व्यापक चुनावी सुधारों की आवश्यकता और संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करने पर चर्चा हुई थी।

हाई कोर्ट के आदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
यहां तक कि जब इस रिपोर्ट की खबर को कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वेबसाइट पर कुछ जूनियर स्टाफ द्वारा डाला गया, तो उसे कुछ ही मिनटों में हटा दिया गया। क्या पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटारसा की इसमें राजीव दत्ता के साथ कोई मिलीभगत है?

यह खबर हटाने का निर्देश देने के पीछे आखिर उनकी रूचि का क्या कारण था? इसके अलावा, हैरानी की बात यह भी है कि कोटा या राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता ने, दिल्ली, जयपुर और कोटा में सत्ता के गलियारों में जो चल रहा है, उस पर कुछ भी नहीं कहा है।

ट्रंप ने भारत पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
की धमकियों के आगे झुकने से दृढ़ता से इनकार कर दिया है। “इस बात को स्वीकार करो या नहीं”, भारत अब दुनिया की प्रमुख भू-राजनीतिक शक्तियों के क्लब में आ गया है और इस पोजीशन के लिए कीमत तो भारत को चुकानी ही पड़ेगी। जब भारतीय नियंत अमेरिकी बाजारों से बाहर हो जाएंगे, तो भारत को दूसरे बाजार तलाशने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जहाँ एक तरफ भारत के अंडिग रुख और अस्थिर स्वभाव वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के आगे झुकने से इन्कार करने की कुछ हल्की सराहना जरूर हो रही है, वहीं, प्रतिक्रियाएं कुछ दबी-दबी हैं, सिवाय व्यापार और भू-राजनीति के, जो अब पूरी तरह एक-दूसरे से जुड़ चुके हैं। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव बिट्कोफ इस समय मॉस्को में पुतिन से बातचीत कर रहे हैं और मंगलवार को दोनों की मुलाकात को क्रेमलिन के प्रवक्ता ने “रचनात्मक” बताया है। भारत, ट्रंप की रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का पहला “भू-राजनीतिक शिकार” बन गया है। भारत की स्थिति यह हो गई है कि

वह अब रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता, ऐसा करना बहुत अधिक झुकना होगा और भारत के अपने हितों को नुकसान पहुंचेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति को होने वाले निर्यात में कुछ असर पड़ने की तुलना में, तेल के वैकल्पिक स्रोत ढूंढना भारत के लिए एक ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। आखिरकार, अमेरिकी नियंत भारत की समग्र अर्थव्यवस्था का बहुत छोटा हिस्सा है और भारत की अर्थव्यवस्था उतनी निर्यात-निर्भर नहीं है, जितनी कुछ अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इस अतिरिक्त टैरिफ के बारे में पहले से ही अनुमान था, लेकिन खास बात यह रही कि ट्रंप ने चीन पर ऐसा कोई शुल्क नहीं लगाया, जिससे एक बार फिर उनकी “टी.ए.सी.ओ.” (ट्रांप् ऑलवेज चिकन्स आउट) अर्थतंत्र ट्रंप हमेशा पीछे हट जाते हैं, वाली छवि चरित्रार्थ होती है। चीन ने बहुत चतुराई से सेकन्डरी प्रतिबंधों से बचाव कर लिया, क्योंकि वह इस समय अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में शामिल है। यह बात तर्क से परे है, क्योंकि चीन तो रूस के युद्ध का कहीं अधिक मुखर और प्रभावी समर्थक रहा है।

महेश जोशी की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए।

याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए 8 अगस्त का समय दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडू की “विद यू स्टालिन” योजना को हरी झंडी दी

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की “विद यू स्टालिन” योजना में वहां के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नाम के इस्तेमाल पर रोक वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बुधवार को रद्द दिया।

इसके साथ ही अदालत ने सरकारी योजना के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले अन्नाद्रमुक सांसद सी.वी. धनमुगम पर अदालत का समय बर्बाद करने के एवज में 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। मुख्य न्यायाधीश जी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने उच्च न्यायालय का आदेश रद्द करते हुए, उसके खिलाफ राज्य सरकार और ट्रिविडु मुनेत्र कडगम (द्रमुक) पार्टी की अपील स्वीकार कर ली। पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा, हमने बार-बार कहा है कि राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जानी चाहिए। अदालतों का इस्तेमाल राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक हिंसा-फिंसाव निपटाने के लिए किया जाना चाहिए। इस अवय को ध्यान ही शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार की विद यू स्टालिन योजना हरी झंडी दे दी।

‘अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए राज्य सरकारें चार हफ्ते में अधिसूचनाएं जारी करें’

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वे अनाथ, कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटे के तहत मुफ्त शिक्षा देने की अनुमति संबंधी अधिसूचनाएं चार सप्ताह के अंदर जारी करें।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और

उत्तरकाशी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के जगह-जगह अवरोध हो जाने के कारण अनेक वाहन अब भी रास्ते में फंसे हुए हैं। हर्षित स्थित सेना के कैंप में भी जबरदस्त नुकसान हुआ है, जिससे क्षेत्र में लॉजिस्टिक चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं। जैसे-जैसे खोज और बचाव कार्य आगे बढ़ रहा है, स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि मृतकों के आँकड़े में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं और कई गांवों से संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है। उत्तरकाशी इस समय हाल के वर्षों की सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदा की चपेट में है।

‘जैसलमेर को तो मुगल भी नहीं जीत पाए थे’

जैसलमेर के पूर्व महारावल चैतन्यराज सिंह ने एन.सी.ई.आर.टी के नक्शे में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का अंग बताने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की

- एन.सी.ई.आर.टी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में पेज क्रमांक 7 पर छपे इस नक्शे में जैसलमेर, बूंदी, मेवाड़ व पंजाब को मराठा साम्राज्य के अधीन बताया गया है।
- मेवाड़ राजघराने के सदस्य व भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, बूंदी राजघराने के ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा, यह हमारे पूर्वजों के बलिदान को धूमिल करने की कोशिश है।

जैसलमेर, 06 अगस्त। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रकाशित आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान विषयक पाठ्यपुस्तक में राजस्थान में जैसलमेर को तत्कालीन मराठा साम्राज्य के मानचित्र में दर्शाए जाने को लेकर जैसलमेर राजपरिवार के पूर्व महारावल चैतन्यराज सिंह ने कड़ी आपत्ति जतायी है। सिंह ने इसे ऐतिहासिक रूप से भ्रामक, तथ्यहीन और गंभीर त्रुटि करार देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इसमें तत्काल संशोधन करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दस्तावेजों, राजकीय अभिलेखों एवं अन्य प्रामाणिक स्रोतों में जैसलमेर में मराठा साम्राज्य के किसी प्रकार के प्रभुत्व, करधान, आक्रमण या हस्तक्षेप का कोई उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत, राजकीय पुस्तकों में भी स्पष्ट उल्लेखित है कि जैसलमेर रियासत में मराठाओं का कभी भी, कोई दखल नहीं रहा। ऐसी स्थिति में एनसीईआरटी जैसी शीर्ष शैक्षणिक संस्था द्वारा इस प्रकार की ऐतिहासिक त्रुटि करना, उसकी

विश्वसनीयता और अकादमिक गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है। सिंह ने कहा कि यह विषय केवल एक मानचित्र की गलती नहीं, बल्कि जैसलमेर की ऐतिहासिक गरिमा, सांस्कृतिक अस्मिता और विद्यार्थियों को दिये जाने वाले ज्ञान की सत्यता से जुड़ा विषय है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस मानचित्र के संबंध में हस्तक्षेप करने की मांग की। राज परिवार के विक्रम सिंह ने बताया कि जैसलमेर के दर्ज इतिहास के अनुसार- मुगल भी जैसलमेर को नहीं

सीजेआई गवई का सीनियर वकीलों को अल्टीमेटम

नई दिल्ली, 06 अगस्त। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी आर गवई ने बुधवार, 6 अगस्त 2025 को साफ कर दिया कि 11 अगस्त से कोई भी सीनियर वकील उनकी अदालत में तत्काल सुनवाई के लिए मामले नहीं ला सकेगा। ऐसा इसलिए किया गया है, जिससे जूनियर वकीलों को ऐसा करने का मौका मिल सके।

सीजेआई गवई ने वकीलों की ओर से तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई

- गवई ने कहा, 11 अगस्त से मेरे कोर्ट में कोई भी सीनियर वकील तत्काल सुनवाई के लिए केस नहीं ला सकेगा।

के लिए मामलों का मौखिक उल्लेख करने की प्रथा को दोबारा शुरू कर दिया था, जिसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बंद कर दिया था। सीजेआई गवई ने कहा, “इस बात की पुर्खोर मांग उठ रही है कि सीनियर वकीलों को किसी भी मामले में तत्काल सुनवाई के लिए मेशन न किया जाए।”

उन्होंने अदालत के कर्मचारियों से कहा कि वे एक नोटिस जारी करें कि सोमवार से उनकी अदालत में किसी भी वरिष्ठ वकील को तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई के लिए मामलों का लाने की इजाजत नहीं होगी।

सीजेआई ने कहा सोमवार से किसी भी सीनियर वकील, किसी भी नामित सीनियर वकील को मामलों का उल्लेख करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जूनियर वकीलों को ऐसा करने का मौका दिया जाना चाहिए।

मैडिकल बोर्ड में 29 में से 24 लोक सेवक दिव्यांग कैटेगिरी के लिए अनफिट निकले

जयपुर, 6 अगस्त । एसओजी ने सरकारी नौकरी में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। एसओजी पुलिस अधीक्षक ज्ञान चंद ने बताया कि विभिन्न स्रोतों से सूचना मिली कि विगत समय से विभिन्न सरकारी नौकरियों में अनेक चयनित उम्मीदवारों ने दिव्यांग नहीं होते हुए भी फर्जी तरीके से बनवाया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है।

सूचना मिलने के बाद एसओजी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मोणा के नेतृत्व में जांच दल गठित कर एसएमएस मैडिकल कॉलेज के विभिन्न विशेषज्ञों का बोर्ड गठित करवा कर दिव्यांग श्रेणी के लोक सेवकों की पुनः मैडिकल जांच करवाई गई, जिसमें 29 दिव्यांग लोक सेवकों की मैडिकल जांच कि रिपोर्ट प्राप्त की, जिसमें से मात्र 5 लोक सेवकों में दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना पाया

- एसओजी ने दिव्यांगत प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी पाने के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया।
- सबसे ज्यादा अनफिट कर्मचारी श्रव्य बाधित श्रेणी में पाए गए।

गया और बाकी 24 तथाकथित दिव्यांगों को मैडिकल बोर्ड ने दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट बताया। श्रव्यबाधित 13 में से 13 लोक सेवक दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट पाए गए। दृष्टिबाधित कथाकथित 8 दिव्यांग में से 6 दिव्यांग कैटेगरी के नहीं पाए गए। इसी तरह लोकोमोटर एवं अन्य प्रकार के 8 लोक सेवकों में से 5 दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट पाए गए।

एक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
एक बयान में बताया कि 1 अक्टूबर से एयर इंडिया के सभी इंटरनेशनल फ्लाइटों की आवाजाही पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। मतलब कि एक अक्टूबर से एयर इंडिया के इंटरनेशनल विमानों की आवाजाही 12 जून से पहले वाली स्थिति में आ जाएगी।

अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया के, इंटरनेशनल के साथ-साथ, घरेलू विमानों की उड़ानों पर भी असर पड़ा था। दुर्घटना के बाद, एयर इंडिया ने सुरक्षा जांच लॉन्च रहने तक अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को आंशिक रूप से रोक दिया था।

समुद्री माल परिवहन बिजल पर संसद की मुहर

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। भारत से शेष दुनिया के समुद्री बंदगाहों तक माल ढ़लाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों और अधिकार तथा छूट से संबंधित प्रावधानों वाले समुद्री माल परिवहन विधेयक को बुधवार को राज्य सभा ने विधेयक के हंगामे के बीच पारित कर दिया। इसके साथ ही, इस विधेयक पर संसद की मुहर लग गयी। इस विधेयक को लोक सभा ने गत 28 मार्च को पारित किया था। राज्य सभा में आज शुद्धकाल के दौरान पहले स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे कार्यवाही पुनः शुरू होने पर विपक्ष

अनफिट पाए गए लोक सेवक हैं- महेन्द्र पाल पुत्र गिरधारी सिंह, तहसील पुलिस थाना भीम राजसबंद; सवाई सिंह गुर्जर टिगरिया का पुरा, हिण्डीन, करौली; हन्टू गुर्जर चंदवाजी जयपुर; मनीष कुमार कटारा बरीली, रुपवास, भरतपुर; केशव उर्फ खूब्याराम रेनवाल; कविता रेनवाल; बिकेश कुमार नदबई; भरतपुर; भानुप्रताप कटारा, रुपवास; नफीस जुहरार, भरतपुर; रणजीत सिंह बयाना, भरतपुर; कलुआ राम बयाना भरतपुर; पवन कुमार आबूरोड सिरौही; विनोद कंवर आबू रोड सिरौही; दिनेश कुमार, धौरीमन्ना बाड़मेर; लोकेश नदबई भरतपुर; संजय नौखा बीकानेर; दीपू डीडवाना, कुचामन; गैंगू बलपुरा पाली; प्रशांत सिंह गांधी नगर सिरौही; हिन्दूपाल सिंह केसरीसिंहपुरा गंगानगर; आसी कुमारी मारुडी, बाड़मेर; डॉ शंकर लाल मीणा देवपुरा बूंदी; विद्यादास चौधरी रुपनगढ़ जिला अजमेर; किशोर सिंह सबलपुर डीडवाना कुचामना

‘वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों का ब्यौरा शनिवार तक पेश करें’

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिए

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह विशेष पुनरीक्षण के दौरान बिहार मतदाता सूची से हटायें गए 65 लाख लोगों (मृत और स्थायी पलायन करने वाले) का विवरण शनिवार तक दे।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्स (एडीआर) की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण की गुहार पर यह निर्देश दिया। पीठ ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा, शनिवार तक जवाब दाखिल करें और भूषण को इसे देखने दें। फिर हम देख पाएंगे कि क्या खुलासा हुआ है और क्या नहीं।

पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी जाएगी।

इस पर चुनाव आयोग के

- चुनाव आयोग ने कहा कि राजनैतिक दलों को यह जानकारी दी गई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन दलों की लिस्ट मांगी जिन्हें यह जानकारी दी गई है।

अधिवक्ता ने कहा कि वह प्रस्तुत करेगा कि यह जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जानकारी साझा की गई है। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि वह अपना जवाब रिकॉर्ड पर रखे। पीठ ने निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता से कहा, उन राजनीतिक दलों की सूची दीजिए, जिन्हें यह जानकारी दी गई है। हम 12 अगस्त को मामले की सुनवाई करेंगे। तब तक अपना (निर्वाचन आयोग का) जवाब दाखिल करें। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की चिंताओं पर कहा, हम यह सुनिश्चित

करेंगे कि प्रभावित होने वाले प्रत्येक मतदाता को आवश्यक जानकारी मिले। एडीआर ने अपने आवेदन में कहा कि 25 जुलाई को निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस विज्ञापन जारी की, जिसमें कहा गया था कि लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। भूषण ने पीठ के समक्ष गुहार लगाते हुए कहा, ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख नामों के छूटने की बात कही गई है, लेकिन इन नामों की कोई सूची नहीं दी गई। इसमें 32 लाख लोगों के पलायन की बात कही गई, लेकिन कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, उन्हें (चुनाव आयोग) यह बताना चाहिए कि 65 लाख लोग कौन हैं? कौन पलायन कर गए हैं। कौन मर गए हैं? जाहिर है, बीएलओ ने उस व्यक्ति को हटाने या न हटाने की सिफारिश की है। भूषण ने दलील दी थी कि चुनाव आयोग ने दो निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है। अन्य क्षेत्रों का क्या हुआ?

एस.सी.ओ. सम्मेलन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
की आवश्यकता के साथ संतुलित करना, भारत-चीन संबंधों की परिपक्वता की परीक्षा होगी। भारत के लिए यह यात्रा चीन की पाकिस्तान नीति पर असंतोष जताने के साथ-साथ व्यापार, तकनीक और बहुध्रुवीय वैश्विक शासन पर साझा सोच तलाशने के लिए भी होगी। मोदी की चीन यात्रा भारत की व्यापक विदेश नीति में एक पुनर्मूल्यांकन का प्रतीक है, जो एक ध्रुवीकृत होते जा रहे विश्व में रणनीतिक लचीलापन बनाए रखने की कोशिश को दर्शाता है। वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग के बीच यह संतुलन भारत की अगली कूटनीतिक दिशा को परिभाषित कर सकता है। इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन में 10 सदस्य देशों के साथ बातचीत में आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार जैसे मुद्दे शामिल रहने की संभावना है।

प्र.मंत्री ने कर्तव्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय होगा। कर्तव्य भवन में पानी की ज़रूरतों के एक बड़े हिस्से को पूरा करने के लिए अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग की व्यवस्था की गयी है। यह भवन 30 प्रतिशत कम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें इमारत को ठंडा रखने और बाहरी

शोर को कम करने के लिए विशेष कांच की खिड़कियां हैं। ऊर्जा-बचत करने वाली एलईडी लाइटें, ज़रूरत न होने पर लाइटें बंद करने वाले सेंसर, बिजली बचाने वाली स्मार्ट लिफ्टें और बिजली के उपयोग को प्रभावित करने की एक उन्नत प्रणाली हैं। कर्तव्य भवन-3 की छत पर लगे सौर पैनल हर साल 5 लाख 34 हजार यूनिट से ज़्यादा बिजली पैदा करेंगे।